सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

वर्ष- 17 अंक - 258 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, बुधवार 01 जुलाई 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

'उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में दिखा दुर्लभ जंगली कुत्तों (ढोल) का झुंड', ट्रैप कैमरे में हुए कैद

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। अखिल भारतीय बाघ आकलन (AITE) 2026 के दौरान उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में लगाए गए कैमरा ट्रैप में चार दुर्लभ भारतीय जंगली कुत्तों (ढोल) का संगठित झुंड रिकॉर्ड हुआ है। वन विभाग ने इसे जंगल के स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और बेहतर वन्यजीव संरक्षण का महत्वपूर्ण संकेत बताया है।

ढोल (भारतीय जंगली कुत्ता) देश के सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त मांसाहारी वन्यजीवों में शामिल है। ढोल झुंड में रहने वाले सामाजिक और अनुशासित वन्यजीव हैं। इनकी मौजूदगी यह दर्शाती है कि टाइगर रिजर्व में शिकार प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है और प्राकृतिक आवास पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित हुआ है। इससे पूरे टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलित और स्वस्थ होने का संकेत मिलता है।

'संरक्षण के लिए प्रभावी कदम'

वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर प्राकृतिक स्वरूप में विकसित करना, वन्यजीव अपराधियों और शिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, एंटी-पोचिंग अभियान को मजबूत करना तथा कैमरा ट्रैप से निगरानी करना शामिल है।

जैव विविधता में बड़ी उपलब्धि

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप संचालक ने बताया कि ढोल के संगठित झुंड का रिकॉर्ड होना यह प्रमाणित करता है कि रिजर्व की खाद्य-श्रृंखला मजबूत हुई है और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित वातावरण विकसित हुआ है। यह उपलब्धि वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में किए गए वैज्ञानिक प्रबंधन, कड़ी सुरक्षा और प्रभावी संरक्षण प्रयासों का परिणाम है।

खास-खबर

नक्सल पीड़ित परिवारों को राहत, 60 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल पर छत्तीसगढ़ शासन ने नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करते हुए नक्सलवाद पुनर्वास नीति के तहत चार नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए कुल 60 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। गौरतलब है नक्सली हिंसा में आम नागरिकों की मृत्यु के ऐसे मामलों में, जहां किसी कारणवश आश्रितों को शासकीय सेवा प्रदान करना संभव नहीं होता, वहां शासन की पुनर्वास नीति के अनुसार शासकीय सेवा के स्थान पर प्रत्येक मृतक के परिजनों को 15 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रावधान के तहत बीजापुर जिले के चार प्रकरणों में कुल 60 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि संबंधित परिवारों के पुनर्वास, आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

अगले शैक्षणिक सत्र के आखिर तक पढ़ा सकेंगे रिटायर शिक्षक

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी और 100त्न अनुदान प्राप्त स्कूलों में काम कर रहे रिटायर शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब ये शिक्षक शिक्षा सत्र 2026-27 खत्म होने तक स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए मंजूरी जारी कर दी है। मंत्रालय से जारी आदेश के मुताबिक, लोक शिक्षण संचालनालय को कहा गया है कि तय नियमों के अनुसार पात्र रिटायर शिक्षकों को जल्द स्कूलों में फिर से पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। इस फैसले का फायदा सरकारी और 100त्न अनुदान प्राप्त स्कूलों को मिलेगा। इससे जहां शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, वहीं छात्रों की पढ़ाई भी बिना रुकावट जारी रह सकेगी। अब सभी जिलों में पात्र शिक्षकों को सत्र 2026-27 के आखिर तक स्कूलों में पढ़ाने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सुनवाई 7 जुलाई को

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक 07 जुलाई 2026 को जांजगीर-चांपा जिले में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि उक्त तिथि को जिला पंचायत के सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक द्वारा प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में बदला बिजली टैरिफ, उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बिल का बोझ, नए नियम भी लागू

■ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी किया गया नया टैरिफ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई यानी बुधवार से बिजली की नई दरें प्रभावी हो गई हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी नए टैरिफ के तहत घरेलू, व्यावसायिक और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को अब पहले की तुलना में अधिक बिजली बिल चुकाना होगा। अधिकांश श्रेणियों में प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 0 से 100 यूनिट तक बिजली की दर 4.10 रुपये से बढ़ाकर 4.40 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। इसी तरह 101 से 200 यूनिट पर 4.50 रुपये, 201 से 400 यूनिट पर 6 रुपये, 401 से 600 यूनिट पर 7 रुपये तथा 600 यूनिट से अधिक खपत पर 8.80 रुपये प्रति यूनिट की दर लागू होगी। व्यावसायिक उपभोक्ताओं की दरों में भी 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि की गई है, जबकि कृषि पंपों के लिए बिजली 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो गई है।

भुगतान संबंधी नियमों में भी किया गया बदलाव

नई टैरिफ व्यवस्था में भुगतान संबंधी नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब अग्रिम बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट 1.25 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, समय पर बिल जमा नहीं करने पर पहले की तरह 1.5 प्रतिशत मासिक सरचार्ज नहीं लगेगा। इसकी जगह अब हर दिन 0.04 प्रतिशत की दर से विलंब शुल्क वसूला जाएगा।

अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने पर भी अतिरिक्त भार

अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने वालों पर भी अतिरिक्त भार बढ़ा है। एलवी-1 और एलवी-2 श्रेणी के अस्थायी कनेक्शनों पर पहले सामान्य टैरिफ का 1.25 गुना शुल्क लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 1.5 गुना कर दिया गया है। हालांकि, बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने राहत भी दी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, पुराने बकाया बिल जमा करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस अवधि में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से विलंब अधिभार (सरचार्ज) नहीं लिया जाएगा।

बकाया जमा करने पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट

इसके अलावा, निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को लंबित बिजली बिल चुकाने में आर्थिक राहत मिलेगी, जबकि नई दरों के लागू होने से बिजली वितरण व्यवस्था को भी वित्तीय मजबूती मिलेगी।

छत्तीसगढ़ में मानसून ने पकड़ी रफ्तार झमाझम बारिश के आसार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। दक्षिण-पश्चिम मानसून अब पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो चुका है और इसके प्रभाव से प्रदेशभर में बारिश का सिलसिला तेज होने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले सात दिनों तक कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। वहीं, बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसम तंत्र के कारण तीन जुलाई के बाद बारिश की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है।

राजधानी रायपुर में बुधवार सुबह से बादलों का डेरा बना हुआ है। बीच-बीच में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को उमस से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार शहर में दिनभर बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण उत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे लगे बांग्लादेश क्षेत्र के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसी सिस्टम के प्रभाव से तीन जुलाई के आसपास उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे छत्तीसगढ़ में वर्षा की गतिविधियां और तेज होंगी।

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए 14 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है।

रायपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में घूसी इनोवा, बड़ा हादसा टला, आरपीएफ ने दर्ज किया केस

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इनोवा पार्सल ऑफिस की ओर से स्टेशन परिसर में दाखिल होकर प्लेटफॉर्म नंबर-1 पार करते हुए रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाती है। कुछ देर के लिए कार ट्रैक के बीच फंसी भी दिखाई देती है। राहत की बात यह रही कि उस समय उस ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं आ रही थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

बताया जा रहा है कि यह घटना दोपहर करीब 1 बजे की है। वीडियो में कार प्लेटफॉर्म से होते हुए ट्रैक की ओर जाती नजर आ रही है।

घटना का वीडियो सामने आने के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। आरपीएफ के मुताबिक, वीडियो सामने आने के बाद वाहन चालक के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 147, 154 और 159 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आपदा : जम्मू-कश्मीर के डोडा में फटा बादल

नईदिल्ली। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश और बादल फटने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। प्राकृतिक आपदा के कारण व्यापक स्तर पर फसलों, बाग-बगीचों और निजी संपत्ति को हानि पहुंची है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है।

डोडा जिले के भलेसा के खलजुगासर इलाके में बादल फटने की घटना हुई। इससे अचानक आई बाढ़ ने कृषि भूमि को बुरी तरह प्रभावित किया है। किसानों की खड़ी फसलें और फलदार बाग-बगीचे पूरी तरह बर्बाद हो गए। कई मकानों और अन्य निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कें बंद हो गईं। इससे भलेसा का भट्यास इलाका घंटों तक शेष क्षेत्रों से कटा रहा।

33 अधिकारियों के तबादले: आदिम जाति विकास विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 33 अधिकारियों का तबादला किया है। इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया गया और सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, प्रभारी CEO, सहायक आयुक्त, क्षेत्र संयोजक और अन्य अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सभी अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। सूची में गरियाबंद, बस्तर, नारायणपुर, सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा, जशपुर, कांकेर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, धमतरी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बलरामपुर के नाम हैं।

इंदौर जा रही बस में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर लगी भीषण आग, आठ की मौत और 24 लोग घायल

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ऋषिकेश से इंदौर जा रही एक स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और ट्रक दोनों में आग लग गई। हादसे में अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं।

दौसा एसपी पीयूष दीक्षित ने बताया कि हादसा कोलवा थाना क्षेत्र के तनावड़ स्थित जीरो पॉइंट पर रात करीब 2:30 बजे हुआ। मृतकों में छह लोगों की मौत आग में झुलसने से हुई, जबकि दो लोगों ने सिर में गंभीर चोट लगने के कारण दम तोड़ दिया। घायलों का इलाज दौसा जिला अस्पताल में चल रहा है। बस में तेजी से फैली आग पुलिस के अनुसार हादसे के बाद बस में आग तेजी से फैल गई, जिससे अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में काफी परेशानी हुई। एसपी पीयूष दीक्षित ने बताया कि अब तक घायलों में से केवल 9 लोगों की पहचान हो सकी है। अन्य यात्रियों की पहचान और उनके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है।

यूपी में बस और कार की टक्कर, पांच लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। बुधवार सुबह करीब पांच बजे एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर कार से टकरा गई। टक्कर के बाद बस डिवाइडर की ग्रिल तोड़ते हुए खंती में पलट गई, जिससे पांच लोगों की जान चली गई। यह दुर्घटना बांगरमऊ कोतवाली इलाके के 230.800 माइल स्टोन के पास हुई। संतकबीरनगर के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली कार में कुल 8 लोग सवार थे। इनमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में दिव्या (13), अमृता (5), अंजू (40), धुनमुन (60) और कार चालक विनोद (45) शामिल हैं। कार में सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें बांगरमऊ सीएचसी से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।

संपादकीय

स्वास्थ्य व्यवस्था में गहरी होती भ्रष्टाचार की जड़ें

जिन अस्पतालों पर एक बड़ी आबादी अपनी बीमारियों के इलाज से लेकर आपात स्थिति में जान बचाने तक के लिए निर्भर होती है, उसे संचालित करने वाले अधिकारी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। आमतौर पर सभी सरकारें जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने का भरोसा देती हैं, लेकिन इस महकमे में पसरी अव्यवस्था और लोगों को होने वाली असुविधाओं के वास्तविक कारणों को दूर करने को लेकर शायद ही कभी संजीदा होती हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों में जिस तरह के घोटाले का खुलासा हुआ, उससे एक बार फिर यही पता चलता है कि सरकारों के लिए आम नागरिकों को एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी स्वास्थ्य तंत्र मुहैया कराने का मुद्दा किस हद तक उपेक्षित है।

> "दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों में जिस तरह के घोटाले का खुलासा हुआ, उससे एक बार फिर यही पता चलता है कि सरकारों के लिए आम नागरिकों को एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी स्वास्थ्य तंत्र मुहैया कराने का मुद्दा किस हद तक उपेक्षित है।
> गौरतलब है कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में दवाओं, शल्य चिकित्सा संबंधी सामग्री सहित अन्य उपकरणों की खरीद में कुछ समय पहले करीब साढ़े छह सौ करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ। अब इसी मामले की छानबीन के क्रम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रविवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के दो पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपों के मुताबिक, स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व महानिदेशक के अधीन संचालित केंद्रीय खरीद एजंसी के जरिए शल्य चिकित्सा से जुड़े उपकरणों और अन्य चिकित्सा सामग्री की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई।

गौरतलब है कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में दवाओं, शल्य चिकित्सा संबंधी सामग्री सहित अन्य उपकरणों की खरीद में कुछ समय पहले करीब साढ़े छह सौ करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ। अब इसी मामले की छानबीन के क्रम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रविवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के दो पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपों के मुताबिक, स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व महानिदेशक के अधीन संचालित केंद्रीय खरीद एजंसी के जरिए शल्य चिकित्सा से जुड़े उपकरणों और अन्य चिकित्सा सामग्री की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई।

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिन अस्पतालों पर एक बड़ी आबादी अपनी बीमारियों के इलाज से लेकर आपात स्थिति में जान बचाने तक के लिए निर्भर होती है, उसे संचालित करने वाले अधिकारी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। यह छिपा तथ्य नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आमतौर पर समाज का वही तबका जाता है, जो निजी अस्पतालों में महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाता है।

सरकारी अस्पतालों में इलाज के क्रम में अक्सर मरीजों को चिकित्सा सामग्री की कमी का सामना करना पड़ता है, उनके परिजनों को अपने पैसे से दवा या अन्य चिकित्सा उपकरण बाहर से खरीदने पड़ते हैं। जबकि सामान्य स्थितियों में अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए दवाओं से लेकर अन्य चिकित्सा सामग्री सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती है। मगर जब संसाधनों की खरीद से जुड़े अधिकारी ही दवा और अन्य जरूरी उपकरणों की खरीद को निजी कमाई और भ्रष्टाचार का जरिया बना लें, तो मरीजों के प्रति उनकी संवेदनहीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

सवाल है कि इस स्तर का भ्रष्टाचार लंबे समय तक कैसे जारी रह पाता है और सरकार के तहत काम करने वाली भ्रष्टाचार निरोधक एजंसी तथा अन्य निगरानी तंत्र क्या कर रहे होते हैं। देश की राजधानी होने के नाते उम्मीद की जाती है कि दिल्ली में शासन-तंत्र अपेक्षया बेहतर तरीके से काम करता होगा और किसी भी महकमे में भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर ज्यादा चौकस होगा। मगर अलग-अलग विभागों में अक्सर जिस तरह की अनियमितताएं सामने आती रही हैं, उससे साफहै कि यहां भी अन्य जगहों की तरह ही भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को समय पर रोक पाना एक मुश्किल काम है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि स्वास्थ्य महकमे में होने वाला घोटाला सीधे-सीधे आम जनता की सेहत और जीवन से जुड़ा मसला है। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर बड़े अस्पतालों तक में चिकित्सा संसाधनों के अभाव के मामले जगजाहिर रहे हैं। साधारण और गरीब तबकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के बजाय अस्पतालों में जारी भ्रष्टाचार पर अगर रोक नहीं लग पा रही है, तो सरकार के जनहित में व्यापक कल्याण कार्यक्रम संचालित करने के दावों को कैसे देखा जाएगा।

भारत और खाड़ी संकट का आर्थिक प्रभाव सब कुछ स्थिर और सामान्य रहा

वी. अनंत नागेश्वरन

जब फरवरी के अंत में हवाई हमलों के कारण हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद हो गया ऐसा समुद्री मार्ग जिससे होकर दुनिया के कच्चे तेल का करीब एक-पांचवां हिस्सा और भारत के कच्चे तेल और खाना पकाने के गैस का अधिकांश हिस्सा गुजरता है तो भारत के लिए कहानी पहले ही लिखी हुई लग रही थी। एक ऐसा देश, जो अपने कच्चे तेल का दस में से नौ हिस्सा और आधे से ज्यादा खाना पकाने के गैस का खाड़ी से आयात करता है, उसके लिए आम तौर पर यही उम्मीद की जा रही थी कि पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगेंगी, रसोई में गैस खत्म हो जाएगी, रुपये की कीमत गिरेगी और डॉलर के लिए होड़ मचेगी। लगभग चार महीने बाद, जब जलडमरूमध्य फिर से खुल गया और कच्चे तेल की आपूर्ति अपने संकट-पूर्व स्तर के करीब पहुँच गयी, तो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। एक भी रिटेल आउटलेट बंद नहीं हुआ। जिस भी परिवार को सिलेंडर चाहिए था, उसे सिलेंडर मिल गया। भारत को न तो 1991 जैसे और न ही 2013 जैसे हालात का सामना करना पड़ा। व्यापक आर्थिक स्थिरता बनी रही।

यह कोई संयोग नहीं था और न ही यह सिर्फ किस्मत की बात थी। यह एक ऐसे सरकार का काम था, जिसने वही तरीका अपनाया, जो उसने महामारी के समय अपनाया था जानबूझकर और धीरे-धीरे कदम उठाना, एक ही बार में कोई बड़ा या नाटकीय बदलाव करने के बजाय एक उपाय के ऊपर दूसरे उपाय को जोड़ना। पहली प्राथमिकता घर-परिवार थे। इस पूरी अवधि के दौरान, एक भी रिटेल आउटलेट का स्टॉक खत्म नहीं हुआ और हर रसोईघर में सिलेंडर मौजूद रहा। आयात से जुड़ी लागत के कारण 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 1,600 रुपये से ऊपर चली गई थी, फिर भी घरों के लिए इसकी कीमत 900 रुपये के आसपास ही रखी गई और सबसे गरीब लोगों के लिए तो यह कीमत और भी कम थी। महामारी के शुरुआती महीनों की यादें एक सबक थीं, जब प्रवासी मजदूरों में मची घबराहट के कारण गांवों की ओर लौटने वालों की लहर चल पड़ी थी। वाणिज्यिक और थोक उपयोगकर्ताओं को घरों की जरूरत को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया।

पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले ईंधन के मामले में, सरकार ने इसका बोझ खुद उठाने का फैसला किया, न कि इसे आम लोगों पर डाला। सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क में दस रुपये प्रति लीटर की कटौती की, जिससे उसे लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ, इसके अलावा विमानन ईंधन पर भी बोझ कम किया गया। इसके बाद तेल विपणन कंपनियों ने दो महीने से ज़्यादा समय तक पंप पर कीमतें स्थिर रखीं और फिर एक बार मामूली बदलाव किया। इसके पीछे की वजह साफ है: ऐसी अनिश्चितता के समय में, सिर्फ़ सरकार के पास ही जोखिम उठाने के लिए ज़रूरी बैलेंस शीट और समय होता है; और इसने परिवारों और कंपनियों पर असर डालने के बजाय राजकोषीय खाते पर बोझ डालने का विकल्प चुना। एयरलाइंस के लिए खास समर्थन तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण-गारंटी योजना, कोविड के दौर में अपनाए गए खास और असरदार उपायों के मॉडल पर ही आधारित थीं।

कीमत में राहत के पीछे आपूर्ति की मजबूत स्थिति थी। घरेलू रिफाइनरियों ने एक हफ्ते में ही रसोई गैस का उत्पादन आधा बढ़ा दिया, जिससे आयात से आने वाली गैस की कमी काफी हद तक पूरी हो गई। भारत ने जल्दी ही अपने स्रोतों का विस्तार किया, अमेरिका और रूस से खरीद बढ़ायी और नए आपूर्तिकर्ता देश जोड़े, ताकि जलडमरूमध्य से होकर कम ऊर्जा आये; साथ ही रूसी कच्चा तेल खरीदना जारी रखने के लिए ज़रूरी छूट भी हासिल कर ली। सरकार ने लंबी अवधि के लिए भी कदम उठाए: घरों को सिलेंडर के बदले पाइप से गैस पहुँचाना, कोयले गैसीकरण कार्यक्रम, ईथेनॉल मिश्रण को और बढ़ावा देना तथा प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान रणनीतिक तौर पर कच्चा तेल भंडारण पर सहमति। भारत उन कुछ देशों में से एक था, जिसने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले जहाजों की संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपना कार्गो लाना जारी रखा।

बाहरी खातों को भी उतने ही धैर्य के साथ संभाला गया। सरकार ने सरकारी कर्ज़ की विदेशी संस्थागत खरीद पर लगी रोक और पूंजीगत लाभ टैक्स हटा दिए और पूर्ण पहुँच रूट के तहत प्रतिभूतियों का दायरा बढ़ाया, जिससे बॉन्ड मार्केट में पैसा आया। एक नई गैर-निवासी डॉलर जमा योजना से काफी बड़ी राशि में डॉलर आने की उम्मीद है। सालों में किए गए मुक्त व्यापार समझौते धीरे-धीरे अपने काम कर रहे थे: अप्रैल और मई 2026 के दौरान गैर-तेल, गैर-रत्न-आभूषण के अलावा वस्तु और सेवाओं का निर्यात पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया।

प्रमुख आंकड़े भरोसा दिलाते हैं। पिछले वित्त वर्ष में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पैंतालीस अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो महामारी के बाद के वर्षों के सत्तर से अस्सी अरब डॉलर की सीमा को पार कर गया। चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 26 में जीडीपी का केवल 0.6 प्रतिशत था और अब उम्मीद है कि वित्त वर्ष 27 में यह इससे थोड़ा ही ज़्यादा होगा।

ईमानदारी से यह भी मानना होगा कि किस्मत ने भी साथ दिया। बंद होने के कुछ ही हफ्तों में कच्चा तेल एक सौ बीस डॉलर के पार पहुंच गया, लेकिन मई से चीन की तेल खरीद में कमी और अमेरिका के रिजर्व से लगातार तेल जारी होने से यह फिर से सौ डॉलर से नीचे आ गया, और चीन के उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करने से बजट को होने वाले भारी नुकसान से बचाया जा सका। अगर संघर्ष लंबे चले होते, या तेल एक सौ बीस डॉलर के करीब स्थिर रहता, तो स्थिति इतनी आरामदायक नहीं होती; ठोस नीति और अच्छी किस्मत दोनों ने अपना काम किया। वास्तव में, किस्मत अंततः ठोस नीतिकारों का ही साथ देती है।

आने वाले बदलावों के संकेत के तौर पर, गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में भारत के लिए अपने वृद्धि पूर्वानुमान को सीवाई 26 के लिए 6.8% और वित्त वर्ष 27 के लिए 6.5% तक बढ़ा दिया है, जो पहले के पूर्वानुमानों से दोनों के लिए 30 बीपी अधिक हैं।

हालांकि, मध्यम अवधि में आत्मसंतोष की कोई गुंजाइश नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ गठबंधन विभाजित हैं, हथियारबंद आपूर्ति श्रृंखलाएँ हैं और ऐसी पूंजी, जो कभी भी आ-जा सकती है, भुगतान संतुलन पर दबाव उस संघर्ष से भी लंबा रह सकता है, जिसने उसे खतरे में डाला था। भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। संतुलित द्विपक्षीय निवेश संधि रूपरेखा, कर नीति में निश्चितता, राज्य सरकारों द्वारा अनुबंधों की अखंडता का सम्मान, भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स और एकल-खिड़की मंजूरी, जो वास्तव में काम करती हो, अब उन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकर्षित करेंगे, जो अपने जोखिम को कम करने के लिए अलग-अलग जगहों पर विस्तार करने की कोशिश कर रही हैं।

असली समस्या आयात पर निर्भरता है और यह सिर्फ़ ऊर्जा से संबंधित नहीं है। माल व्यापार घाटा राष्ट्रीय आय का लगभग आठ प्रतिशत है; अगर तेल निकाल दें, तो यह पांच प्रतिशत है; तेल और सोना निकाल दें, तो भी यह साढ़े तीन प्रतिशत रहता है। तुलनात्मक रूप से बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। भारत को उन चीज़ों का उत्पादन देश में ही करना चाहिए जिन्हें वह प्रतिस्पर्धी ढंग से बना सकता है और जिनकी उसे ज़रूरत है। देश की कंपनियों और व्यापार संघों को अपने समझौतों पर ज्यादा मेहनत करना होगा — खासकर यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के नए समझौते, जो इस साल लागू होंगे और श्रम-गहन निर्यात को बढ़ावा देंगे। यह सब कुशल लोगों के बिना संभव नहीं है, इसलिए युवाओं को व्यापार से जुड़े कौशल सिखाने का काम अब युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए।

इन कामों के लिए लगन और तेज़ी की ज़रूरत होगी। इन पर ध्यान देते हुए, सरकार को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पर भी ध्यान देना होगा जिसने अब तक निराश किया है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन पर भी विचार करना होगा कि भारतीय काम और भारतीय जीवन के लिए इसके मायने क्या होंगे। खाड़ी संघर्ष ने एक प्रकार की सहनशीलता की परीक्षा ली; आने वाले साल दूसरे प्रकार की परीक्षाएं लेंगे। भारत ने पहली परीक्षा को अच्छे ढंग से पूरा किया। यह आत्मविश्वास का एक कारण है और अगले काम में लगने का भी कारण है।

वी. अनंत नागेश्वरन भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं।

देश, समाज, जीवन की फिक्र भी पढ़ाई का जरूरी हिस्सा है

प्रियदर्शन

देश में जल्द ही विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर खुलने वाले हैं- यह बात उन छात्रों को सुकून देने वाली है, जो अंतरराष्ट्रीय तौर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढना तो चाहते हैं लेकिन जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे बाहर रहने का खर्च उठाकर यह कर सकें। आने वाले वर्षों में ऐसे छात्र इन विश्वविद्यालयों से लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन क्या इससे भारतीय उच्च शिक्षा के माहौल में गुणात्मक परिवर्तन होगा?

झारखंड के एक विश्वविद्यालय की प्रोफेसर बताती हैं कि वहां अब मनोविज्ञान विषय की पढ़ाई बंद हो गई है, क्योंकि पहले मनोविज्ञान के प्राध्यापक नहीं रहे और फिर छात्रों ने दाखिला लेना बंद कर दिया। अंततः विश्वविद्यालय ने कोर्स से ही मुक्ति पा ली। एक दूसरे कॉलेज की प्राध्यापिका बताती हैं कि उनके यहां बैचलर स्तर के अलग-अलग कोर्स में हिंदी के 3000 विद्यार्थी हैं, लेकिन पढ़ाने वाली बस एक शिक्षिका हैं।

ये सूचनाएं किसी अपवाद की तरह नहीं आ रही हैं। एक दौर में तमाम सरकारी विश्वविद्यालयों में अच्छे प्रोफेसर होते थे, सारी अराजकता के बावजूद छात्र पढ़ते थे। वह अराजकता भी उनके व्यक्तित्व निर्माण में कुछ योगदान ही देती थी। वे दुनिया में अपनी विशेषज्ञता के लिए नाम कमाते थे। लेकिन धीरे-धीरे इस तंत्र में जंग लग गई। कुलपति योग्यता नहीं, राजनीतिक अनुकम्पा के आधार पर चुने जाने लगे। अब तो प्राध्यापकों की चयन प्रक्रिया में भी यह कसौटी बताई जाती है कि वे किसी खास विचारधारा के समर्थक हों।

कभी कहा जाता था कि विश्वविद्यालय समाज के वे ठिकाने होते हैं, जहां 15-16 साल की उम्र में बहुत सारे संभावित अपराधी दाखिल होते हैं, लेकिन अगले चार-पांच बरस में जिम्मेदार नागरिक बनकर निकलते हैं। इन ठिकानों में उन्हें तमाम विषयों का ज्ञान मिलता था, राजनीतिक समझ मिलती थी, कुछ याद रह जाने लायक प्रोफेसर मिलते थे, कुछ आंदोलनों और कुछ शरारतों की स्मृतियां मिलती थीं और उनके व्यक्तित्व में अगर कोई अतिरिक्त तीक्ष्णता होती थी तो उसे तराशकर मानवीय बनाने का काम होता था।

लेकिन अब पढ़ाई एक कारोबार में बदल गई है। अब स्कूलों से बारहवीं पास करके लड़के विश्वविद्यालयों नहीं, तकनीकी संस्थानों में जा रहे हैं, जहां से चार साल में डिग्री लेकर उन्हें एक चमकती हुई नौकरी हासिल करनी है। उन्हें देश, समाज, जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचना है, किसी आदर्श के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस कोर्स पूरा करना है और कैम्पस सिलेक्शन के जरिए कहीं निकल जाना है।

लेकिन पढ़ाई बस इतने के लिए नहीं होती। विश्वविद्यालय बेहतर नागरिक बनाने के कारखाने भी होते हैं। यह नागरिकता रसायन, भौतिकी या गणित से ज्यादा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र पढ़ कर आती है, जिन्हें आर्ट फैकल्टी या मानविकी संकाय कहा जाता है। सबसे ज्यादा दुर्दशा इसी संकाय की हुई है।

यह हमेशा से माना जाता रहा है कि पढ़ने में होशियार बच्चे साइंस लेते हैं, लेकिन यह इन वर्षों में ही हुआ है कि आर्ट्स की पढ़ाई जैसे धूल में मिला दी गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले इतिहास, भूगोल या राजनीति के प्रश्नों के लिए तैयारी कराने का काम अब कोचिंग संस्थानों का है।

भारत में स्कूली शिक्षा तो पहले से सामाजिक असमानता का आधार रही, लेकिन अब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक भी शैक्षणिक विषमता का यह सिलसिला पहुंच गया है। निजी विश्वविद्यालयों की चमक-दमक तो बहुत है लेकिन वहां न शिक्षकों को पूरे पैसे मिलते हैं और न छात्रों को पूरा ज्ञान। इस अंधकार में जुगनू की तरह आ रहे विदेशी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के हमारे वास्तविक संकट को कितना हल कर पाएंगे- यह एक बड़ा सवाल है। विश्वविद्यालय बेहतर नागरिक बनाने के कारखाने होते हैं। यह नागरिकता रसायन, भौतिकी या गणित से ज्यादा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र पढ़ कर आती है, जिन्हें आर्ट फैकल्टी कहा जाता है। पर सबसे ज्यादा दुर्दशा इसी संकाय की हुई है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भारत में नागरिकता साबित करने के दस्तावेज का सवाल

एस. वाई. कुरैशी

विदेश मंत्रालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा का दस्तावेज़ है, न कि नागरिकता का पक्का सबूत। स्वतः संज्ञान वाले इस बयान ने एक पुरानी अहम बहस को फिर जिंदा कर दिया: क्या भारत को नागरिकता के प्रमाण लिए किसी एक, पक्के सबूत की ज़रूरत है?

लोगों की प्रतिक्रिया हैरानी भरी थी। यदि पासपोर्ट भी पक्का सबूत नहीं, तो फिर क्या है? क्या आधार नागरिकता का सबूत है? क्या वोटर आईडी कार्ड है? क्या कोई ऐसा दस्तावेज़ है जो इस सवाल को हमेशा के लिए सुलझा दे? सीधा जवाब है- नहीं। भारत में कभी भी नागरिकता का कोई एक, सर्वमान्य दस्तावेज़ नहीं रहा। उलझन इसलिए पैदा होती है कि हम तीन अलग-अलग अवधारणाओं, पहचान, निवास और नागरिकता, को एक ही मान लेते हैं। वे आपस में जुड़ी हैं, लेकिन एक जैसी नहीं। आधार कार्ड पहचान व निवास की पुष्टि करता है। पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में सहायक है। वोटर आईडी कार्ड वोट देने की पात्रता बनाता है। इनमें कोई भी सभी उद्देश्यों के लिए नागरिकता का कानूनी व पक्का सुबूत नहीं, हालांकि आखिरी दो केवल नागरिकों को ही जारी किए जाते हैं।

भारत में नागरिकता 'नागरिकता अधिनियम, 1955' के मुताबिक तय होती है और यह जन्म, वंशावली, पंजीकरण या देशीयकरण(तय न्यूनतम अवधि तक निवास) के ज़रिए मिलती है। व्यावहारिक तौर पर, इसे किसी एक पक्के प्रमाण-पत्र की बजाय कई रिकॉर्ड्स का मिलान कर स्थापित किया जाता है। अनेक देश नागरिकों का रजिस्टर रखते हैं या नागरिकता पहचान पत्र जारी करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव के पास ऐसे कार्ड हैं। अधिकांश यूरोपीय देशों में भी ऐसा है। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश हैं, वहां मामला जन्म रिकॉर्ड, पासपोर्ट और अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ों पर निर्भर है। भारत बाद वाले देशों जैसा है : हमारे पास कई पहचान प्रणालियां हैं, लेकिन नागरिकता का कोई एक सर्वमान्य सबूत नहीं।

आधार कार्ड का अनुभव सीखने लायक है। साल 2009 में शुरू किए गए आधार कार्ड को निवासियों की विशिष्ट पहचान के साधन के तौर पर डिज़ाइन किया गया था, ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बेहतर ढंग से पहुंचाया जा सके और दोहरापन खत्म हो। इसे जानबूझकर नागरिकता से अलग रखा गया था, नहीं पता क्यों। इसका नामांकन निवास के आधार पर किया गया था, न कि राष्ट्रीयता के। नतीजतन, आधार कार्ड कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा। मुझे लगता है, यह एक चूक थी। इसे दोहरे उद्देश्य वाले दस्तावेज़ के तौर पर बनाना चाहिए था।

नागरिकता पर बहस सबसे नाटकीय ढंग से असम में फिर उभरी। जहां एनआरसी सर्वे सिर्फ़ पहचान साबित करने की प्रक्रिया नहीं थी; यह राज्य में अवैध रूप से आकर बसने के इतिहास से जुड़ी नागरिकता की जांच-पड़ताल प्रक्रिया थी। 1985 के असम समझौते के तहत

निवासियों को सबूत देना था कि वे या उनके पूर्वज 24 मार्च, 1971 से पूर्व भारत में मौजूद थे।

सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुई इस प्रक्रिया में हज़ारों अधिकारी शामिल थे, करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए और पांच साल चली। फिर भी, नतीजा बहुत विवादित रहा। 2019 में जारी अंतिम सूची से करीब 19 लाख आवेदक बाहर कर दिये । जो लोग एनआरसी की मांग कर रहे थे, उनके मुताबिक, इसमें अभी भी अवैध प्रवासी ले लिये, जबकि बाहर किए कई लोगों का दावा था कि असली नागरिक छोड़ दिए। अंतिम आधिकारिक सूची अभी अधिसूचित नहीं की व अधर में है।

तो यह प्रक्रिया विफल क्यों रही? इसका जवाब पुरानी तारीखों से नागरिकता साबित करने की जटिलता में छिपा है। लाखों आम भारतीयों को जैसे गरीब, प्रवासी, महिलाएं, भूमिहीन मज़दूर और बाढ़ विस्थापित- दशकों पुराने दस्तावेज़ी सबूत पेश करने में मशक्कत करनी पड़ी। नाम में अंतर, रिकॉर्ड न मिलना या शादी के बाद नाम चेंज जैसी चीज़ों ने और मुश्किलें पैदा की। जब तीन करोड़ से ज़्यादा लोगों से आधी सदी से पुराने रिकॉर्ड के ज़रिए नागरिकता साबित करने को कहा जाए तो त्रुटियां स्वाभाविक है।

अक्सर दी जाने वाली दलील कि पासपोर्ट या वोटर कार्ड जाली भी हो सकते हैं, लेकिन तब तो यह तर्क एनआरसी में जमा किए गए किसी भी दस्तावेज़ पर समान रूप से लागू होता है। जालसाज़ी का मुद्दा बेहतर जांच-पड़ताल वाली व्यवस्था बनाने की मांग करता है, न कि किसी दस्तावेज़ को खारिज करने की। असम का अनुभव एक बड़ा सवाल खड़ा करता है: अगर 3.3 करोड़ आबादी वाले एक राज्य में ही इतनी मुश्किलें आईं, तो क्या 145 करोड़ लोगों के साथ पूरे देश में ऐसी प्रक्रिया बिना बड़ी परेशानी संभव होगी? यहां सवाल सिर्फ प्रशासनिक नहीं; जनता पर भरोसे का भी है।

चुनाव आयोग में छह साल बिताने के बाद, मैं जानता हूं कि नागरिक किसी भी ऐसी प्रक्रिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हैं जिसे वे बोझिल या खुद को बाहर कर दिए जाने वाली मानते हों। मतदाता सूची के हालिया 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' से जुड़े विवाद यही दर्शाते हैं। लोगों को सत्यापन से दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है जब बार-बार पुराने दस्तावेज़ दिखाने और दफ्तर -दफ्तर भागने को कहा जाये। साथ ही, नागरिकता से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया का विरोध तब होगा जब नागरिकों को लगेगा कि इसका मकसद चुनिंदा लोगों पर लागू करना या दंडित करना है। जनता को सुविधा मिले, न कि परेशानी। तो क्या भारत को नागरिकता का पक्के सबूत का विचार छोड़ देना चाहिए? कदापि नहीं। इसके लिए संसद ने पहले ही रास्ता दिखा रखा है। साल 2003 में संशोधित नागरिकता कानून में हर नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण, भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की बात कही गई है। संलग्न नियमों में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाना, तदनुसार सत्यापन एवं एनआरसी तैयार करने का प्रावधान था। इस तरह, कानूनी ढांचा करीब दो दशक से मौजूद है। कमी रही है क्रियान्वयन की नागरिक-हितैषी रूपरेखा बनाने और इसे निष्पक्ष एवं बिना जल्दबाजी लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति की।

वह रूपरेखा दो आधारों पर टिकी हो। पहला, जन्म का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन यह भविष्य के नागरिकता रिकॉर्ड का आधार बनना चाहिए। इसके लिए मैं दोहरे तरीके का सुझाव देता हूं: एक, जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है , उन्हें सीधे-सीधे नागरिकता कार्ड दिया जा सकता है। दो, पुरानी पीढ़ियों के लिए, सरकार मुख्य रूप से मौजूदा रिकॉर्ड पर निर्भर रहे- वोटर लिस्ट, पासपोर्ट, सरकारी सेवा रिकॉर्ड, टैक्स फाइलिंग, पेंशन रिकॉर्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्र। ये दस्तावेज़ दशकों से सरकार द्वारा अपने नागरिकों को दी गई मान्यता दर्शाते हैं। कोशिश सबको साथ लेकर चलने की हो, न कि शक की। नागरिकता साबित करने का बोझ बार-बार आम नागरिकों पर नहीं पड़े; सरकार की ज़िम्मेदारी हो कि वह ठोस आधार पर साबित करे कि अमुक व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति पर सचमुच शक है। भले ही इसमें 5-10 साल लगें।

अवैध आप्रवासन एक वास्तविक चुनौती है और इसके गंभीर उपाय करने ज़रूरी भी हैं। लेकिन जो तरीके अपनाए जाएं, वे निर्दिष्ट और सबूत आधारित हों; न कि ऐसी जल्दबाजी वाली कार्रवाई, जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ने को बनाए सरकारी जाल में लाखों असली नागरिक फंस जाएं और उन्हें परेशान होना पड़े। नागरिकता, व्यक्ति और राज्य के बीच का बुनियादी रिश्ता है। राष्ट्र को निश्चित ही पता होना चाहिए कि उसके नागरिक कौन हैं और कौन नहीं,लेकिन यह काम इस ढंग से हो जिससे लोगों को भरोसा मिले, न कि डर जाएं; सबको साथ लेकर चलने वाला हो, न कि जानबूझकर बाहर करने वाला; और वह, जिससे नागरिक एवं राज्य के बीच भरोसे का रिश्ता मजबूत होता हो।

लेखक भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रमुख खबरें

विधानसभा प्रश्नों के उत्तर भेजने में सहयोग हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

दुर्ग। छत्तीसगढ़ विधानसभा का षष्ठम विधानसभा के दशम् सत्र 13 जुलाई 2026 से प्रारंभ होकर 17 जुलाई 2026 तक आयोजित है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने विधानसभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के लिये जिले के अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर त्वरित गति से जवाब भेजने के लिये जिला कार्यालय दुर्ग हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्टर के आदेशानुसार अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह को नोडल अधिकारी तथा डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सहायक नोडल अधिकारी को विधानसभा प्रश्नों की जानकारी समय-सीमा में प्राप्त कर नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

जिला सहकारी विकास समिति की बैठक संपन्न

दुर्ग। देश में सहकारिता मंत्रालय के स्थापना की 05 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 29 जून से सहकारी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें प्रस्तावित गतिविधियों के अंतर्गत कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सहकार से समृद्धि योजना अंतर्गत सहकारी समितियों के विस्तार हेतु रायशुमारी की गई। मत्स्य एवं दुग्ध समिति के गठन पर जोर देते हुए समितियों के विस्तार के साथ समिति सदस्यों को सक्षम बनाने हेतु विभागीय प्रयास करने के निर्देश दिये गये। बैठक में एडीएम वीरेन्द्र सिंह, जिला पंचायत के सीईओ बजरंग दुबे, उपायुक्त सहकारी संस्थाएं सतीश पाटले, उप संचालक मत्स्य सीमा चन्द्रवंशी, उप संचालक पशुपालन एवं दुग्ध विकास डॉ. वसीम सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

उच्चतम न्यायालय के लंबित प्रकरणों का होगा समाधान

दुर्ग। माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत द्वारा न्याय को जनसामान्य तक सुलभ, सरल एवं सहभागी स्वरूप में उपलब्ध कराने की अभिनव पहल समाधान समारोह, 2026 के अंतर्गत समापन चरण में दिनांक 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति, संवाद एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करना है, ताकि पक्षकारों को सहज, मानवीय एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जिन पक्षकारों को इस संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ है, वे निर्धारित तिथि की प्रतीक्षा किए बिना पूर्व में ही मध्यस्थता केन्द्र, दुर्ग में संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पक्षकार दूरभाष, ई-मेल अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क स्थापित कर अपने प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण निराकरण हेतु आवश्यक जानकारी एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

भिलाई 3-चरोदा निगम में भाजपा का हल्ला बोल
कांग्रेस की शहर सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के निर्देशानुसार भाजपा भिलाई-3 एवं चरोदा मंडल तथा नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा के भाजपा पार्षदों के संयुक्त तत्वावधान में कांग्रेस शासित नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा की कथित निरंकुश कार्यशैली, भ्रष्टाचार, जनविरोधी नीतियों एवं विकास कार्यों में अनियमितताओं के विरोध में विशाल जंगी धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना स्थल भाजपा कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के जोशपूर्ण नारों से गूंज उठा। वक्ताओं ने महापौर परिषद को भ्रष्टाचार, कुशासन और जनता की उपेक्षा के मुद्दे पर घेरते हुए नगर निगम की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला।

मुख्य वक्ता एवं भाजपा जिला संगठन प्रभारी रामजी भारती ने कहा कि कांग्रेस की शहर सरकार जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। नगर निगम में विकास कार्य ठप हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है और आम नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई जारी रहेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने कहा कि नगर निगम में पारदर्शिता और जवाबदेही समाप्त हो चुकी है। पेयजल संकट, जर्जर सड़कें, सफाई व्यवस्था की बदहाली, स्ट्रीट लाइट की समस्या और विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं ने जनता का विश्वास तोड़ दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनसमस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भाजपा आंदोलन को और व्यापक रूप देगी।

भाजपा जिला प्रवक्ता प्रेम लाल साहू ने अपने प्रभावी संबोधन में कहा कि कांग्रेस की शहर सरकार ने विकास के नाम पर केवल घोषणाएं की जबकि धरातल पर भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का बोलबाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में योजनाओं की क्रियान्वयन में पक्षपात, वित्तीय अनियमितताओं, और जनहित की अपेक्षा की लगातार शिकायतें सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि भाजपा जनता की आवाज बनाकर प्रत्येक वार्ड की समस्याओं को संघर्ष के माध्यम से उठाती रहेगी और भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर छिपने नहीं देगी। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री उपकार चंद्राकर ने कहा की कांग्रेस की गलत नीतियों का सबसे अधिक नुकसान गरीब, पिछडे, श्रमिक और मध्यवर्ग की परिवारों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता अब परिवर्तन का मन बना चुकी है और बीजेपी जन-जन की आवाज बनकर लोकतांत्रिक संघर्ष को निरंतर आगे बढ़ाएगी।

विधायक प्रतिनिधि सतीश साहू ने कहा की नगर निगम की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए हैं तथा जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है उन्होंने कहा कि भाजपा का संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं बल्कि जनता के अधिकारों और पारदर्शी प्रशासन की स्थापना के लिए है। सभा को पूर्व महापौर चंद्रकांता मांडले, पूर्व नपाध्यक्ष सीता साहू, नेता प्रतिपक्ष रामखेलावन वर्मा, उप नेता प्रतिपक्ष चंद्र प्रकाश पांडेय , सचेतक तुलसी ध्रुव तथा पार्षद फिरोज फारूकी, अपर्णा दास गुप्ता, सत्य प्रकाश शर्मा, तुशांत वर्मा एवं संजय यादव ने संबोधित किया और नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए जनहित के मुद्दों पर जवाब देही तय करने की मांग की।

इस अवसर पर मंच पर वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभुनाथ मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष महेश वर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य-बृजेश बिचपुरिया, रवि शंकर सिंह, शिरीष अग्रवाल, निहारिका मिश्रा, पूर्व नपाध्यक्ष द्वय - शशिकांत बघेल एवं सीता साहू , मंडल प्रभारी द्वय- विजेंद्र सिंह एवं मनोज तिवारी, सांसद प्रतिनिधि-विपिन चंद्राकर, विधायक प्रतिनिधि- दिलीप पटेल, मंडल अध्यक्ष द्वय- वरुण यादव एवं ए गौरी शंकर, पार्षदगण- नंदिनी जांगड़े, कुसुम चंद्राकर, राकेश बंछोर सहित जिला पदाधिकारी- चन्ना केशवलु, विनोद सिंह, दया सिंह, शैलेन्द्र सिंह, भाजयुमो जिलाध्यक्ष- सौरभ जायसवाल, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष- स्वीटी कौशिक, भाजपा नेता तरुण परघनिया एवं बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जन प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री एवं मंडल प्रभारी मनोज तिवारी ने किया तथा आभार प्रदर्शन मंडल अध्यक्ष- वरुण यादव ने किया। पूरे व्यवस्था दोनों मंडल के महामंत्री श्याम सुंदर जायसवाल, समीर अग्रवाल, पूर्णिमा ठाकुर एवं राजेश मौर्य ने सम्हाल रखे थे । कार्यक्रम के अंत में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नगर निगम में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्यवाही तथा पेयजल, सड़क, सफाई, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य जन समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने की मांग की।

भिलाई की बसाहट बचाने जन-जन तक पहुंचे विधायक देवेंद्र, सेक्टर-2 से शुरू किया जनसंपर्क

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भिलाई टाउनशिप की बसाहट और शहर की पहचान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सोमवार को भिलाई की बसाहट बचाओ जनसंपर्क अभियान की शुरुआत सेक्टर-2 से की। अभियान के पहले दिन उन्होंने पार्षदों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ घर-घर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और टाउनशिप को बचाने की इस मुहिम में सहयोग एवं समर्थन देने की अपील की।

विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि बीएसपी प्रबंधन द्वारा टाउनशिप में रहने वाले लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। साथ ही सेक्टर-9 अस्पताल सहित बीएसपी क्षेत्र की बसाहट को कमजोर कर निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भिलाई की पहचान, यहां की सामाजिक संस्कृति और वर्षों से बसे परिवारों के भविष्य पर किसी भी प्रकार का संकट स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे भिलाई के अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई है।

इसलिए सभी नागरिकों को धर्म, जाति और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर एकजुट होना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि पूरा शहर साथ खड़ा होगा तो भिलाई की बसाहट को कोई भी नहीं उजाड़ पाएगा। अभियान के तहत सेक्टर-2 के वार्ड-56, सड़क-15 तथा वार्ड-55, सड़क-12 में बैठकें आयोजित की गईं। विधायक ने स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि उनके अधिकारों और भिलाई की बसाहट की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा।

विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि यह अभियान आगे भी टाउनशिप के प्रत्येक सेक्टर और हर घर तक पहुंचेगा। वे स्वयं लोगों से लगातार संवाद करेंगे और सभी के सहयोग से भिलाई की बसाहट, सेक्टर-9 अस्पताल तथा शहर की विरासत को बचाने की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। जनसंपर्क अभियान में पार्षद साधना सिंह, विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र परघनिया, रमाकांत देशलहरे, सेक्टर-4 के राजेश चौधरी, सेक्टर-3 के पार्षद सुरेश वर्मा, हरिश सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक शामिल हुए।

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 27 स्वयं सहायता समूहों को 1.08 करोड़ का बैंक ऋण वितरित

दुर्ग। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में विकासखंड पाटन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा की रानीतराई एवं दिग्गाभाठा शाखाओं के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने हेतु सतत समन्वय एवं अनुश्रवण किया गया। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल से जून 2026 की अवधि में कुल 27 स्वयं सहायता समूहों को 1,08,50,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित किया गया। बैंक ऋण वितरण से स्वयं सहायता समूहों के उद्यम विकास, स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्धन को नई गति मिलेगी। इससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुदृढ़ होगी तथा वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा की रानीतराई एवं दिग्गाभाठा शाखाओं में संध्या पखवाड़ा - SHG Login Day, कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं, ऋण प्रक्रिया, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिंग एवं उद्यमिता विकास की जानकारी प्रदान की गई।

किसानों को मिली राहत, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिलेगा यूरिया खाद

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। राज्य सरकार के फैसले से जिले के किसानों को बड़ी राहत मिली है। खरीफ 2026 के दौरान किसानों को यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सहकारी क्षेत्र में यूरिया वितरण संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यूरिया की वर्तमान पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए पूर्व में जारी कुछ प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है।

नए निर्देशों के अनुसार अब पात्र किसानों को खरीफ 2025 में प्राप्त यूरिया की मात्रा के बराबर ही खरीफ2026 में भी यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा।

उप संचालक कृषि संदीप भोई ने बताया कि किसानों को यह उर्वरक एकमुश्त अथवा संबंधित सहकारी समिति में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर चरणबद्ध तरीके से वितरित किया जाएगा। सहकारी समिति मे यूरिया की अल्प उपलब्धता की स्थिति में कृषक की पत्रातानुसार यदि यूरिया प्राप्त किया जाना शेष हो, तो शेष मात्रा समिति में यूरिया उपलब्ध होने पर प्राप्त की जा सकेगी।

जिले में किसान भाईयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर अभिजित सिंह के मार्गदर्शन में सतत् भंडारण एवं वितरण की कार्यवाही की जा रही है। जिले में खरीफ2026 हेतु कुल 67880 मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में सहकारी एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर जिले में 22688 मीट्रिक टन यूरिया, 4376 मीट्रिक टन डीएपी, 11725 मीट्रिक टन एनपीके, 5901 मीट्रिक टन एमओपी तथा 11067 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट कुल 55757 मीट्रिक टन उर्वरक भंडारण किया गया है एवं सेवा सहकारी समितियों एवं निजी विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को लगातार उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। अब तक 11986 मीट्रिक टन यूरिया, 3431 मीट्रिक टन डीएपी, 5371 मीट्रिक टन एनपीके, 3612 मीट्रिक टन एमओपी तथा 7161 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट कुल 31561 मि.टन उर्वरक का वितरण किया जा चुका है तथा वर्तमान में जिले में 10701 मीट्रिक टन यूरिया, 946 मीट्रिक टन डीएपी, 6354 मीट्रिक टन एनपीके, 2289 मीट्रिक टन एमओपी तथा 3906 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट कुल 24196 मि.टन उर्वरक शेष है। जिले में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है तथा किसी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है।

जिले के सभी किसान भाईयों से अपील की गई है कि फसलों के बेहतर उत्पादन एवं भूमि कि सेहत के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित संतुलित खाद का ही उपयोग करें। किसान भाई अपनी पात्रता के अनुसार निकटतम सहकारी समिति से संपर्क कर सुगमतापूर्वक यूरिया का उठाव कर सकते हैं।

अधोसंरचनात्मक कार्यों की बेस लाईन सर्वे हेतु जानकारी देवें अधिकारी
जनशिकायत संबंधी आवेदनों का करें त्वरित निराकरण - कलेक्टर अभिजीत सिंह

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में विभागवार समय-सीमा के लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा की। साथ ही लंबित आवेदनों का निराकरण समयावधि में करने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, जनशिकायत पोर्टल के लंबित आवेदनों के निराकरण की जानकारी लेते हुए कहा कि जनशिकायत संबंधी आवेदनों का अधिकारी त्वरित निराकरण करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने जनशिकायत से संबंधित आवेदन लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी। कलेक्टर सिंह ने सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत विभागों को प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। साथ ही एल-1 अधिकारी को समय-सीमा के भीतर प्रकरण निराकृत करने कहा। विभागीय अधिकारियों ने सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत तकनीकी दिक्कतों से अवगत कराया। कलेक्टर श्री सिंह ने ई-डिस्ट्रिक मैनेजर को उच्च स्तर पर आवश्यक पहल करने के निर्देश दिये हैं।

कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों में राजस्व प्रकरण अविवादित, नामांतरण, बंटवारा पंजीयन की जानकारी ली। साथ ही पंचायत सचिवों द्वारा राजस्व प्रकरणों के पंजीयन उपरान्त रिकार्ड दुरूस्ती पर जोर देते हुए एसएलआर को पंचायतों में पंजीकृत प्रकरणों के रिकार्ड दुरूस्ती कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय प्रयोजन हेतु विभागों को भू-आबंटन के लंबित प्रकरण होने पर संबंधित विभाग राजस्व विभाग को प्रकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि भू-आबंटन की कार्यवाही में प्रगति लायी जा सके। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम एवं अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने सीएमएचओ को एनएचएम भर्ती काउंसलिंग तिथि पश्चात उसी दिन नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिये। इसके अलावा शेष अन्य पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कराने निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि जिले में अधोसंरचनात्मक निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने विभागीय बेस लाइन सर्वे अंतर्गत नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों से जानकारियां मंगायी जा रही है। संबंधित विभाग के अधिकारी अधिनस्त अधिकारियों को उक्त जानकारी मय हस्ताक्षर के साथ संबंधित निकायों/जनपद को उपलब्ध कराने निर्देशित करें।

बैठक में एडीएम वीरेन्द्र सिंह, जिला पंचायत के सीईओ बजरंग दुबे, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पांडे, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त सुमीत अग्रवाल, नगर निगम रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा, एसडीएम दुर्ग हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम पाटन लवकेश ध्रुव सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

खास-खबर

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में रिक्त संविदा पदों पर भर्ती

रायगढ़। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छर्राटांगर, विकासखंड घरघोड़ा, जिला रायगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संविदा आधार पर रिक्त पदों की भर्ती हेतु 3 जुलाई 2026 को प्रात: 8 बजे से विद्यालय परिसर में वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह संविदा आधार पर होगी और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने तक की जाएगी। रिक्त पदों में पीजीटी राजनीति विज्ञान, पीजीटी इतिहास, पीजीटी अर्थशास्त्र और काउंसलर के एक-एक पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों का अंग्रेजी माध्यम (सीबीएसई) में दक्ष होना अनिवार्य है तथा एनईएसटीएस एवं ईएमआरएस के निर्धारित मानकों के अनुसार होगी। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि इससे पहले भी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया गया था, लेकिन उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पद रिक्त रह गए थे। शैक्षणिक गतिविधियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए पुन: भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट emrschharratangar.in पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से किसानों को बड़ी राहत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराने और खेती को अधिक सुगम बनाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में खरीफसीजन 2026 के लिए जांजगीर-चांपा जिले के किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकारी समितियों के माध्यम से यूरिया वितरण पर लागू 80 प्रतिशत की सीमा समाप्त कर दी गई है। अब किसानों को खरीफ 2025 की भांति उनकी पात्रता के अनुसार एकमुश्त यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। उप संचालक कृषिराकेश शर्मा ने बताया कि खरीफ 2026 में किसानों को खरीफ2025 में प्राप्त यूरिया की मात्रा के अनुरूप यूरिया वितरित किया जाएगा। यदि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहेगा तो किसानों को एकमुश्त यूरिया प्रदान किया जाएगा। किसी समिति में स्टॉक की कमी होने पर शेष मात्रा यूरिया उपलब्ध होते ही किसानों को वितरित कर दी जाएगी।

डीएईएसआई के नए बैच हेतु नामांकन 15 जुलाई तक

बिलासपुर। कार्यालय परियोजना संचालक (आत्मा) सह उप संचालक कृषि द्वारा DAESI (Diploma in Agricultural E&tension Services for Input Dealers) के नवीन बैच के लिए पात्र इच्छुक उम्मीदवार एवं इनपुट डीलरों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिले के सभी विकासखंडों बिल्हा, तखतपुर, मस्तूरी एवं कोटा के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के इच्छुक एवं पात्र इनपुट डीलरों से आवेदन प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित 15 जुलाई 2026 तक कार्यालय परियोजना संचालक (आत्मा), बिलासपुर को भेजना सुनिश्चित करें। आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र न्यूनतम 10+2 या नियमानुसार पात्रता, आधार कार्ड, पासपोर्ट रंगीन फोटो, निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। कृषि विभाग ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है, ताकि नए बैच में प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूर्ण की जा सके।

सीएम हेल्पलाइन का कमाल, डेढ़ माह से लंबित समस्या का 6 घंटे में हुआ समाधान

- शादी के बाद पत्नी के आधार अपडेट की समस्या हुई दूर
- राशन कार्ड में नाम जोड़ने का रास्ता हुआ आसान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का आधिकारिक और टोल-फ्री नंबर 1076 है। इस नंबर का उपयोग राज्य के नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कराने, सुझाव देने और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन, जवाबदेह प्रशासन और नागरिकों को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम लोगों के लिए भरोसे का सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण बालोद जिले के ग्राम बोरी निवासी श्री टेमन लाल साहू के मामले में देखने को मिला, जहां लगभग डेढ़ माह से लंबित उनकी समस्या का समाधान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के महज 6 घंटे के भीतर कर दिया गया। टेमन लाल साहू का विवाह लगभग तीन माह पूर्व हुआ था। वे अपनी पत्नी का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए आधार कार्ड में पति का नाम और वर्तमान पता अपडेट होना आवश्यक था। आधार में यह संशोधन कराने के लिए वे पिछले डेढ़ महीने से लगातार विभिन्न सेवा केंद्रों के चक्कर लगा रहे थे।

सोशल मीडिया से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की मिली जानकारी

इसी दौरान उन्हें बालोद जिला प्रशासन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होते ही जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने स्वयं हितग्राही से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए। प्रशासन की त्वरित एवं संवेदनशील कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप जिस कार्य के लिए हितग्राही डेढ़ माह से परेशान था, वह केवल 6 घंटे में सफलतापूर्वक पूरा हो गया। आधार कार्ड में आवश्यक संशोधन होने के बाद अब टेमन लाल साहू अपनी पत्नी का नाम आसानी से राशन कार्ड में जुड़वा सकेंगे, जिससे उन्हें विभिन्न शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी समय पर मिल सकेगा।

एक फोन कॉल से घंटों में हुआ काम

अपनी खुशी व्यक्त करते हुए टेमन लाल साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि जो काम डेढ़ माह से नहीं हो पा रहा था, वह एक फोन कॉल के बाद कुछ ही घंटों में पूरा हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की यह पहल आम जनता को त्वरित राहत दिलाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। उन्होंने अन्य नागरिकों से भी अपील की कि यदि किसी शासकीय कार्य में अनावश्यक विलंब हो रहा हो या प्रशासनिक समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का अवश्य उपयोग करें।

विकसित भारत-जी राम जी योजना से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई दिशा

ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिनों के रोजगार की गारंटी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। देशभर में 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना लागू हो रही है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका संवर्धन और आधारभूत विकास को नई गति देने के उद्देश्य से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत -2047 के विज़न को साकार करने की दिशा में ग्रामीण भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाना है। योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, आजीविका संवर्धन और गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को मांग के आधार पर वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, कृषि आधारित कार्य, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका संवर्धन जैसे टिकाऊ कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। विकसित ग्राम की परिकल्पना को साकार करने के लिए योजना में कुल 318 प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2026-27 के बजट में 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2 जुलाई को होगा शुभारंभ

छत्तीसगढ़ में योजना के शुभारंभ एवं क्रियान्वयन को लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 जुलाई 2026 को तिरुपति, आंध्रप्रदेश से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें वे देश के विभिन्न राज्यों से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम कबीरधाम के ग्राम पंचायत गंडईखुर्द में आयोजित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ग्रामीणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से संवाद करेंगे।

ग्राम सभा की भूमिका सशक्त

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी, 15 दिवस के भीतर मजदूरी भुगतान की व्यवस्था होगी, कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। इसी तरह डिजिटल जॉब कार्ड एवं तकनीक आधारित कार्य प्रबंधन प्रणाली, समयबद्ध एवं पारदर्शी भुगतान व्यवस्था के साथ ग्राम सभा की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाया गया है।

ग्राम सभा द्वारा तैयार की जाएगी विकास कार्यों की कार्ययोजना

वीबी जीरामजी में जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण सड़क, वृक्षारोपण एवं टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। इस योजना से ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास एवं आजीविका के नए अवसर प्रदान करेगी। सामाजिक अंकेक्षण एवं डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता में भी वृद्धि होगी। नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की कार्ययोजना ग्राम सभा के माध्यम से तैयार की जाएगी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों का चयन किया जा सकेगा। विकसित भारत-जी राम जी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और गांवों में विकास की स्थायी आधारशिला तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर साक्ष्य-आधारित नीति व गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के महत्व पर हुआ मंथन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा आज इंद्रावती भवन, नवा रायपुर में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ों के महत्व, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण तथा प्रशासनिक आंकड़ों के प्रभावी उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संचालक श्री तीर्थराज अग्रवाल ने कहा कि विश्वसनीय सांख्यिकीय आंकड़े प्रभावी नीति निर्माण, सुशासन और समावेशी विकास की मजबूत आधारशिला हैं। मुख्य अतिथि प्रो. प्रीति के. सुरेश (डायरेक्टर, MMTTC) तथा प्रो. धर्मेंद्र कुमार गंगेश्वर (विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय) ने भी नीति निर्माण, अनुसंधान और विकास योजनाओं के सफ्ल क्रियान्वयन में सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़ों की भूमिका पर प्रकाश डाला। अपर संचालक श्री एन. बुलीवाल ने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की प्रासंगिकता एवं सांख्यिकी की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला।

तकनीकी सत्र में उप संचालक श्री दिनेश कुमार तिवारी ने "Unlocking Potential Administrative Data" विषय पर प्रस्तुति देते हुए प्रशासनिक आंकड़ों के बेहतर उपयोग की संभावनाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया। इसके पश्चात प्रतिभागियों द्वारा प्रशासनिक आंकड़ों के उपयोग एवं MLALADÓs Online Portal पर प्रस्तुतियां दी गईं।

अचार के स्वाद में घुली आत्मनिर्भरता बिहान ने बदली महिलाओं की जिंदगी

- कभी घर तक सीमित थीं, आज अपने उत्पाद से कमा रही हैं सम्मान और आय

श्रीकंचनपथ न्यूज

कबीरधाम। जिले के सहसपुर लोहारा की कुछ महिलाओं ने शायद कभी नहीं सोचा था कि रसोई में बनने वाला आम का अचार एक दिन उनकी पहचान बन जाएगा। जो महिलाएं पहले केवल घर-परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित थीं, वे आज अपने हाथों से तैयार अचार के जरिए न केवल परिवार की आय बढ़ा रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई मिसाल भी बन गई हैं। इस बदलाव की मजबूत नींव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ने रखी।

सहसपुर लोहारा के माँ जगदंबा स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने अपने आसपास उपलब्ध आम को आजीविका का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। शुरुआत आसान नहीं थी। बाजार, पैकेजिंग और व्यवसाय का अनुभव नहीं था, लेकिन बिहान के तहत मिले प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सामूहिक प्रयास ने उनकी सोच और जिंदगी दोनों बदल दी। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं ने गुणवत्ता के साथ आम का अचार तैयार करना शुरू किया। धीरे-धीरे स्थानीय बाजार में उनके उत्पाद की मांग बढ़ने लगी। आज समूह की महिलाएं स्वयं अचार तैयार करती हैं, उसकी पैकेजिंग करती हैं और बाजार तक पहुंचाकर बिक्री भी करती हैं। इस उद्यम से उन्हें नियमित आय मिल रही है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और उनका आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ा है।

समूह की महिलाओं का कहना है कि पहले वे केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, लेकिन अब अपनी मेहनत से कमाई कर परिवार की जिम्मेदारियों में बराबरी से भागीदारी निभा रही हैं। उनकी पहचान अब केवल गृहिणी के रूप में नहीं, बल्कि सफल महिला उद्यमी के रूप में भी बनने लगी है।

शाला प्रवेशोत्सव : शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने बच्चों संग बैठकर सिखाया पहाड़ा, स्मार्ट क्लास का किया लोकार्पण

- नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत, गणवेश व जूते वितरित कर दी शुभकामनाएं

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। शाला प्रवेशोत्सव के अंतर्गत शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव मंगलवार को दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के बोरसी स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, आदर्श कन्या शाला एवं जेआरडी विद्यालय में आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर एवं मिठाई खिलाकर आत्मीय स्वागत किया तथा नवीन शिक्षा सत्र के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विद्यार्थियों को गणवेश एवं जूते भी वितरित किए गए।

शिक्षा मंत्री यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों से संवाद करते हुए बच्चों की नियमित पढ़ाई, विद्यालय में शत-प्रतिशत उपस्थिति तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की पहली पाठशाला उनका परिवार होता है और अभिभावकों का सहयोग ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा देता है। विद्यालय में स्थापित स्मार्ट क्लास का लोकार्पण करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगी तथा उन्हें भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सक्षम बनाएगी।

कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री यादव सीधे कक्षाओं में पहुंचे और बच्चों के बीच बैठकर उनसे आत्मीय संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से पहाड़े सुने और स्वयं भी सरल एवं रोचक तरीके से उन्हें पहाड़ा सिखाया। साथ ही बच्चों को पढ़ाई को आनंददायक बनाने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्होंने उनके सपनों, भविष्य की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों पर चर्चा की तथा मन लगाकर अध्ययन करने, अनुशासन का पालन करने और निरंतर मेहनत से आगे बढ़ने का संदेश दिया।

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने छात्राओं एवं शिक्षकों से भी संवाद करते हुए शिक्षा के साथ संस्कार, आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व विकास के महत्व पर बल दिया। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए छात्राओं से पूरी लगन, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ अध्ययन कर अपने परिवार, समाज एवं प्रदेश का नाम गौरवान्वित करने का आह्वान किया।

जन-जागरूकता से बचा एक किशोरी का भविष्य, बाल विवाह की सूचना मिलते ही प्रशासन ने की त्वरित कार्रवाई

मुख्यमंत्री के सशक्त नेतृत्व में बाल विवाह रोकथाम अभियान को मिल रही सफलता

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान का सकारात्मक परिणाम अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। बीजापुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे जन-जागरूकता अभियान के चलते एक 15 वर्षीय किशोरी का संभावित बाल विवाह समय रहते रोक दिया गया।

भोपालपटनम विकासखंड के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी के विवाह की सूचना जागरूक नागरिकों ने समय रहते चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 पर दी। सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची।

समझाइश से बदला परिजनों का निर्णय

अधिकारियों ने किशोरी के माता-पिता, परिजनों और ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। समझाइश और विधिक परामर्श के बाद परिजनों ने बाल विवाह नहीं करने तथा बालिका की पढ़ाई जारी रखने की सहमति दी। साथ ही भविष्य में बाल विवाह नहीं कराने का लिखित आश्वासन भी दिया।

जागरूकता अभियान का दिख रहा सकारात्मक असर

जिला प्रशासन ने बताया कि जिले में लगातार ग्राम स्तरीय बैठकों, विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों, सामुदायिक संवाद और व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण लोगों में बाल विवाह के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि अब नागरिक स्वयं आगे आकर ऐसी घटनाओं की सूचना दे रहे हैं।

समय पर सूचना देकर बचाएं बच्चों का भविष्य

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह एक सामाजिक और कानूनी अपराध है। यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) या 181 (महिला हेल्पलाइन) पर सूचना दें।

जनसहयोग से मिलेगा बाल विवाह मुक्त समाज

जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस विभाग ने जागरूक नागरिकों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं, जनजागरूकता और जनभागीदारी के समन्वित प्रयासों से ही बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। समय पर दी गई एक सूचना किसी बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सकती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बच्चों के सुरक्षित, शिक्षित और उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इससे पूरे प्रदेश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने में विभाग को मदद मिल रही है।

श्वेता तिवारी ने रेड ड्रेस में बिखेरा जलवा, स्माइल से लूट लिया करार

श्वेता तिवारी सिर्फएक एक्टिव और टैलेंटेड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि स्टाइल आइकन भी हैं। उनके फैशन सेंस में सिंपल और एलिगेंट का परफेक्ट मिक्स नजर आता है जो हर मौके पर उनके लुक को परफेक्ट बनाता है। चाहे रैड कार्पेट हो या कैजुअल आउटिंग, श्वेता हमेशा अपनी स्टाइल और ग्रेस से लोगों को इंप्रेस करती हैं। उनके इस इंस्टाग्राम पोस्ट में भी ये साफ दिखाई देता है कि वो फैशन और परफॉर्मेंस दोनों में बराबर एक्सील करती हैं।

श्वेता तिवारी हमेशा से ही अपने स्टाइल और परफॉर्मेंस के लिए फैंस के बीच काफी पॉपुलर रही हैं। इस इंस्टाग्राम पोस्ट में उनका लुक देखते ही बनता है। श्वेता रेड कलर की लेयर्ड ड्रेस में नजर आ रही हैं जो उनके स्टाइल और ग्रेस को और निखार रही है। ड्रेस की फ्लोइंग लेयर्स उनके मूवमेंट के साथ खूबसूरती से झूल रही हैं और उनका सिंपल लेकिन एलिगेंट स्टाइल उन्हें मॉडर्न और क्लासिक दोनों तरह का लुक दे रहा है। उन्होंने अपने लुक को गोल्डन ईयररिंग्स और पेस्टल हील्स के साथ कंप्लीट किया है जो उनकी पर्सनालिटी को और हाईलाइट कर रहे हैं। उनके बाल खुले और सॉफ्ट वेव्स में सेट हैं, जो उनके चेहरे की खूबसूरती को और निखारते हैं। उनके नेचुरल पोज ने तस्वीर को और भी खास बना दिया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो श्वेता तिवारी ने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत बेहद कम उम्र में की थी और धीरे-धीरे खुद को टॉप टीवी एक्ट्रेस बन गई थी। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान कसौटी जिंदगी की की प्रेरणा के रूप में मिली, जहां उन्होंने प्रीति का रोल निभाया। इसके अलावा श्वेता ने कई रियलिटी शो जैसे कि खतरों के खिलाड़ी और झलक दिखला जा में नजर आई थी। टीवी सीरियल्स के अलावा, उन्होंने वेब शोज और प्रिंट कमर्शियल्स में भी अपने एक्टिंग स्किल्स को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। उनकी परफॉर्मेंस हमेशा ही नेचुरल और दिल को छू लेने वाली रही है जिससे फैंस उनके हर प्रोजेक्ट में जुड़े रहते हैं।

इक्का में सनी देओल और अक्षय खन्ना के बीच सबसे बड़ी जंग, 10 जुलाई को होगा महा-मुकाबला

बॉलीवुड के 2 दिग्गज कलाकार सनी देओल और अक्षय खन्ना जल्द ही एक धमाकेदार कोर्टरूम ड्रामा फिल्म में आमने-सामने नजर आने वाले हैं। नेटफ्लिक्स ने उनकी आगामी फिल्म इक्का का एक बेहद दमदार और नया पोस्टर जारी कर दिया है, जिसके साथ ही फिल्म की आधिकारिक रिलीज तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। आइए जानते हैं अक्षय खन्ना और सनी देओल के कड़क अंदाज से सजी ये फिल्म किस दिन दर्शकों के बीच आएगी।

सनी और अक्षय पूरे 29 साल बाद एक बार फिर स्क्रीन शेयर करने के लिए तैयार हैं। नेटफ्लिक्स ने अब फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया है। ये फिल्म 10 जुलाई को सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। यह फिल्म एक दमदार और कड़क कानूनी ड्रामा है। इसकी कहानी में कोर्ट के अंदर होने वाली आम बहसों के बजाय किरदारों की सोच, उनके सही-गलत के फैसलों और मन में चलने वाली कशमकश को दिखाया गया है।

सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के निर्देशन और अल्केमी फिल्म्स के बैनर तले बनी इक्का से सनी देओल ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर वह अपने दमदार अंदाज में लौटेंगे, लेकिन इस बार कहानी कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में तिलोत्तमा शोम और दीया मिर्जा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। इक्का एक बड़ी कानूनी लड़ाई की कहानी है, जिसमें विचारधाराओं का टकराव, सही-गलत का द्वंद्व और किरदारों का अतीत आपस में जुड़ा हुआ है।

रणवीर सिंह की 'प्रलय' को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट

'धुरंधर' की सफलता के बाद फैंस रणवीर सिंह की अगली बड़ी फिल्म 'प्रलय' के बारे में अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्ममेकर जय मेहता की जॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है। अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि फिल्म की शूटिंग इस साल के आखिर में शुरू हो सकती है। साथ ही फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में शूट किया जाएगा।

पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'प्रलय' की शूटिंग सितंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर ने इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। एक सोर्स ने पिंकविला को बताया, 'रणवीर 2026 के दूसरे हाफ में जय मेहता के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में होगी और उन्होंने तैयारी शुरू भी कर दी है। फिल्म के बड़े पैमाने और जॉनर को देखते हुए इसके लिए जबरदस्त फिजिकल और इमोशनल तैयारी की जरूरत है।

रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का प्री-प्रोडक्शन अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, जहां जय मेहता और उनकी टीम उन टेक्नीशियन्स के साथ मिलकर काम कर रही है जो पहले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेकर्स प्रोडक्शन शुरू होने से पहले फिल्म की विशाल पोस्ट-एपोकैलिप्टिक दुनिया बनाने पर ध्यान दे रहे हैं।

फिल्म में वीएफएक्स का होगा जबरदस्त इस्तेमाल

रिपोर्ट के अनुसार, 'प्रलय' काफी हद तक विजुअल इफेक्ट्स पर निर्भर करेगी और राइटिंग टीम स्क्रीनप्ले और फिल्म की बड़ी जॉम्बी दुनिया को बेहतर बनाने का काम जारी रखेगी। कहा जा रहा है कि रणवीर भी डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान क्रिएटिव चर्चाओं में एक्टिव रूप से शामिल हैं।

रणवीर की सबसे महंगी स्टैंडअलोन फिल्म होगी 'प्रलय'

खबरों के मुताबिक, लगभग 300 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली 'प्रलय' रणवीर सिंह के करियर की सबसे महंगी स्टैंडअलोन फिल्म हो सकती है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि कल्याणी प्रियदर्शन को फीमेल लीड के तौर पर कास्ट किया गया है, जो बॉलीवुड में उनका डेब्यू होगा।

'उन्हें इसमें दिलचस्पी थी कि गाएगी, नाचेगी, बारिश में भीगेगी'

अपनी बोल्ड इमेज पर जीनत अमान ने तोड़ी चुप्पी

जीनत अमान 70 के दशक की दिग्गज अभिनेत्री हैं। उन्होंने कई चर्चित फिल्मों में काम किया। ग्लैमरस और बोल्ड भूमिकाओं के लिए उन्हें खास पहचान मिली। हाल ही में अदाकारा ने सिनेमा की दुनिया में बनी अपनी बोल्ड छवि पर बात की। दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान का 1970 के दशक में खूब जादू चला। स्क्रीन पर ग्लैमरस और लीक से हटकर किरदार निभाने की वजह से उन्हें 'बोल्ड' एक्ट्रेस जैसे नाम मिले। इन किरदारों के चलते दशकों तक उनकी पब्लिक इमेज बोल्ड और ग्लैमरस अभिनेत्री की रही। हालांकि, जीनत का कहना है कि ये किरदार कभी उनकी असल पर्सनैलिटी को नहीं दिखाते थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी ऑन-स्क्रीन इमेज और असल पर्सनैलिटी के बीच के अंतर के बारे में बात की।

'फिल्म मेकर्स को लुक्स में ज्यादा दिलचस्पी थी'

जीनत अमान ने अपनी बोल्ड इमेज पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि फिल्ममेकर्स उनके क्रिएटिव इनपुट के बजाय उनके लुक्स में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। जीनत ने अपने यूट्यूब चैनल पर शुभ्रा अयप्पा के साथ एक इंटरव्यू में कहा, 'मुझे हमेशा लगा कि मेरे बारे में जो दिखाया जाता था और मैं असल में जैसी थी, उन दोनों में बहुत फर्क था। बोल्ड अभिनेत्री का ठप्पा मुझ पर बहुत लंबे समय तक लगा रहा। जब लोग मुझसे मिलते थे, तो उन्हें एहसास होता था कि मैं असल में उन किरदारों जैसी बिल्कुल नहीं थी जिन्हें मैंने निभाया था।

'लीड एक्ट्रेस थी, पर मेरी नहीं चलती थी'

जीनत अमान ने दौर में इंडस्ट्री में काम करने के बारे में बात करते हुए बताया कि सेट पर ज्यादातर पुरुषों का ही बोलबाला होता था। अपने हेयरड्रेसर के अलावा, अक्सर वही एकमात्र महिला होती थीं। लीड एक्ट्रेस होने के बावजूद उन्होंने कहा कि अपने किरदारों को गढ़ने या उन्हें दिखाने के तरीके में उनकी बहुत कम चलती थी, क्योंकि ध्यान ज्यादातर उनके लुक पर ही रहता था। जीनत के मुताबिक, किसी को भी मेरे दिमागी काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें तो बस इसमें दिलचस्पी थी कि ये गाएगी,, नाचेगी, दो डायलॉग बोलेगी, बारिश में भीगेगी।

जीनत ने अपने फैशन सेंस और इस बारे में भी बात की कि कैसे अमेरिका से भारत लौटने के बाद ग्लोबल ट्रेंड्स ने उनके स्टाइल पर असर डाला। उन्होंने कहा कि कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम अक्सर भानु अथैया जैसे मशहूर डिजाइनरों के साथ मिलकर किया जाता था। हालांकि, उन्होंने बताया कि अक्सर उनके अपने सुझाव फिल्ममेकर्स की चाहत के मुकाबले ज्यादा संयमित होते थे। जीनत अमान ने इंडस्ट्री में असमान वेतन के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि इस अंतर की वजह पितृसत्तात्मक व्यवस्था में छिपी है।

असमान वेतन पर क्या बोलीं जीनत?

अभिनेत्री के मुताबिक, कमर्शियल सिनेमा में आर्थिक फैसले पारंपरिक रूप से पुरुषों के हाथ में रहे हैं। इससे जेंडर पे गैप की समस्या पैदा हुई है। अभिनेत्री ने कहा, 'सच कहूं तो, मुझे लगता है कि ज्यादातर आर्थिक ताकत पुरुषों के हाथ में है। पैसे-कौड़ी का काम पुरुष ही संभालते हैं और हमारा समाज आज भी पुरुष-प्रधान है। कमर्शियल सिनेमा भी इसी बात को ध्यान में रखकर फिल्में बनाता है। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि इंडस्ट्री ने पिछले कुछ समय में थोड़ी तरक्की की है, लेकिन बदलाव बहुत धीरे-धीरे आया है।

फर्श की टाइल्स का रंग हो गया है पीला? इन 5 तरीकों से दोबारा करें सफेद

फर्श की टाइल्स को साफ रखना एक मुश्किल काम हो सकता है, खासकर जब उनका रंग पीला पड़ने लगे। यह समस्या आमतौर पर गंदगी, तेल और अन्य गंदे पदार्थों के कारण होती है, जो टाइल्स के ऊपर जमा हो जाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप बिना ज्यादा मेहनत के अपने फर्श की टाइल्स को फिर से चमकदार और सफेद बना सकते हैं।

बेकिंग सोडा और पानी का करें इस्तेमाल

फर्श की टाइल्स को साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा और पानी का घोल बना सकते हैं। इसके लिए एक कप बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को टाइल्स पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर इसे ब्रश से रगड़ें। इससे गंदगी और दाग हट जाएंगे और टाइल्स फिर से चमकदार हो जाएंगी। यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि सुरक्षित भी है, क्योंकि इसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं होता है।

सिरका और पानी का बनाएं मिश्रण

सिरका और पानी का घोल भी फर्श की टाइल्स को साफ करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में 2-3 कप सफेद सिरका मिलाएं और इस मिश्रण को स्पंज या झाड़ू की मदद से पूरे फर्श पर फैलाएं। कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें, फिर साफ पानी से धो लें। इससे न केवल टाइल्स की गंदगी हटेगी, बल्कि उनका रंग भी फिर से चमकदार हो जाएगा।

नींबू के रस का करें उपयोग

नींबू का रस प्राकृतिक रूप से सतह को सफेद करने वाला होता है, जिसे आप टाइल्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक नींबू काटकर उसका रस सीधे दाग वाले हिस्से पर निचोड़ें और कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर ब्रश से रगड़ें। दाग आसानी से हट जाएंगे और टाइल्स का रंग भी फिर से चमकदार हो जाएगा। ये तरीका न केवल असरदार है, बल्कि सुरक्षित भी है, इसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं होता है।

हाइड्रोजन पेरॉक्साइड आएगा काम

हाइड्रोजन पेरॉक्साइड एक शक्तिशाली क्लीनर होता है, जिसे आप फर्श की टाइल्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक कप हाइड्रोजन पेरॉक्साइड को 2 कप पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें और इसे दाग वाले हिस्से पर स्प्रे करें, फिर ब्रश से रगड़ें। इससे दाग आसानी से हट जाएंगे और टाइल्स का रंग भी फिर से चमकदार हो जाएगा। इसे इस्तेमाल करने के बाद एक बार पानी से दोबारा टाइल्स साफ कर लें।

सॉफ्ट ब्रश या स्पंज होगा उपयोगी

फर्श की टाइल्स को साफ करने के लिए सॉफ्ट ब्रश या स्पंज का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, ताकि उन पर खरोंच न आएं। कठोर ब्रश या झाड़ू का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे टाइल्स पर खरोंच पड़ सकती हैं और उनका रंग भी फीका पड़ सकता है। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप फर्श की टाइल्स को आसानी से साफ कर सकते हैं और उनका रंग फिर से चमकदार बना सकते हैं।

खास खबर

सहकार से समृद्धि का गूंजा संदेश

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प और केंद्र में सहकारिता मंत्रालय के गठन के पाँच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुंगेली जिले में सहकारिता सप्ताह का उत्साहपूर्वक शुभारंभ हुआ। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक जिले में विभिन्न जनजागरूकता एवं जनभागीदारी आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जिले की 70 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, दुग्ध एवं मत्स्य सहकारी समितियों में सहकारी ध्वज फहराया गया। इस दौरान सभी समितियों में सामूहिक रूप से सहकार गीत का गायन कर सहयोग, सहभागिता और सामूहिक विकास का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, किसानों, जनप्रतिनिधियों और समिति सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सहकारिता आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बताया गया कि सहकारिता केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार भी है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य सहकारिता की भावना को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना, अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता आंदोलन से जोड़ना तथा सामूहिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

सेवा-सेतु केंद्र बना भरोसे का माध्यम, कुसुम पटेल का बना विवाह प्रमाण पत्र

रायपुर। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से अब लोगों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसका सकारात्मक लाभ मुंगेली जिले के बरेला निवासी कुसुम पटेल को भी मिला, जिनका विवाह प्रमाण पत्र सेवा-सेतु केंद्र के माध्यम से सहज और समयबद्ध रूप से बन गया। पहले विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को लेकर उन्हें कई तरह की जानकारी और औपचारिकताओं की चिंता थी, लेकिन सेवा-सेतु केंद्र में आवश्यक मार्गदर्शन और सरल प्रक्रिया के कारण उनका आवेदन आसानी से पूरा हुआ और उन्हें समय पर विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा कि सेवा-सेतु केंद्र की व्यवस्था से न केवल समय और श्रम की बचत हुई, बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुविधाजनक भी रही। उन्होंने राज्य शासन के इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि इससे आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। पहले जहां लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 73 सेवाएं उपलब्ध थीं, वहीं अब सेवा-सेतु केंद्रों के जरिए 442 डिजिटल सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जा रही हैं। इस नई व्यवस्था से शासन की सेवाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। नागरिकों का समय, श्रम और संसाधनों की बचत होने के साथ-साथ सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और त्वरित उपलब्धता भी सुनिश्चित हो रही है। सेवा-सेतु केंद्र राज्य शासन की डिजिटल सुशासन की सोच को साकार करते हुए नागरिकों और शासन के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य कर रहे हैं।

दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का समापन समारोह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सराबोर रहा। कार्यक्रम में स्कूली छात्र-छात्राओं एवं कलाकारों ने लोकनृत्य, नाटक व गीत-संगीत की शानदार प्रस्तुतियाँ दीं। पूरे वातावरण में उत्साह, भक्ति और उल्लास की मनोहारी छटा बिखरी रही। कार्यक्रम में श्री राम के भक्तिमय गीत-संगीत की प्रस्तुतियों से वातावरण राममय हुआ।

श्री राम के भक्तिमय गीत-संगीत की प्रस्तुतियों से राममय हुआ वातावरण

इस दौरान जांजगीर चाम्पा जिले के शांति प्रतिमा डांस ग्रुप की महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका की शानदार प्रस्तुति ने खूब तालियां बटोरीं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय लखनपुर की छात्राओं ने मेघदूतम पर आधारित नृत्य नाटिका की मनमोहक प्रस्तुत दी। वहीं साई म्यूजिकल पारम्परिक नृत्य समूह ने हनुमान जी की लीला, रामभजन एवं शबरी प्रसंग पर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। प्रकाश रसीला ने लोक गीत एवं वाद्य यंत्र की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में स्टार रूप ने सामूहिक नृत्य, शास्वती बनर्जी ने नृत्य, जागृति म्युजिकल ग्रूप (विस्वा) ने लोक संगीत, कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय ने बैंड, कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय ने राजस्थानी नृत्य, शा.उ.मा. विद्यालय सलका उदयपुर ने सरगुजिहा नृत्य, कन्या छात्रावास उदयपुर ने आदिवासी नृत्य, सेजेस उदयपुर द्वारा सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिरमिटी उदयपुर ने सामूहिक नृत्य, वियशी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय झिरमिटी उदयपुर ने सामूहिक नृत्य, बृजेश शर्मा ने भजन, संदीप गोस्वामी ने लोक गीत भजन, लालसाय सरगुजिहा पार्टी ने छतीसगढ़ी लोक नृत्य, बीजीएम म्युजिकल ग्रूप ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। देर शाम तक चले इन कार्यक्रमों ने दर्शकों को उत्सव स्थल पर बांधे रखा।

जंगल सफारी, प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीवों की रोमांचक साइटिंग से पर्यटकों का बढ़ा आकर्षण

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है भोरमदेव जंगल सफारी में। 'ईको-टूरिज्म' के तहत स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना लोगों को प्रकृति से जोड़ने की नई पहल शुरू की गई है, जिसमें पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शानदार मॉडल शामिल हैं।

जंगल सफारी प्रकृति प्रेमियों और रोमांच के शौकीनों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है, सिर्फ एक माह में ही 489 से अधिक पर्यटक यहां पहुंचे हैं, वहीं स्थानीय युवाओं, वन प्रबंधन समिति और स्व-सहायता समूहों को रोजगार एवं आमदनी के नए अवसर मिले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में शुरू की गई यह जंगल सफारी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है। वन मंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि भोरमदेव जंगल सफारी का उद्घाटन 3 मई को कर पर्यटकों के लिए इसका संचालन शुरू किया गया था। मानसून को देखते हुए, 4 जून से सफारी को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है।

मात्र एक माह के संचालन के दौरान 480 से अधिक पर्यटकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया, जिससे पौने 3 लाख रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। भोरमदेव जंगल सफारी की शुरुआत से स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर मिले हैं। केवल एक महीने के संचालन में वाहन चालक, गाइड और गेट कीपर के रूप में कार्यरत 17 स्थानीय युवाओं ने 75 हजार रुपये से अधिक की आय अर्जित की। वहीं वन प्रबंधन समिति को 92 हजार और वन विभाग को 26 हजार रुपये से अधिक का आय प्राप्त हुई। एक माह में कैंटीन से 20 हजार रुपये से अधिक का मुनाफा हुआ, जिससे समूह की महिलाओं की आय बढ़ी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूती मिली। जंगल सफारी के साथ-साथ भोरमदेव का प्राकृतिक उद्यान भी पर्यटकों की पसंद बन रहा है।

निर्माणाधीन बिलासपुर-उरगा खंड पर आम वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर (एनएच-130A) के निर्माणाधीन बिलासपुर-उरगा खंड पर आम नागरिकों एवं सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह खंड अभी निर्माणाधीन है तथा तकनीकी रूप से सामान्य यातायात के लिए चालू नहीं किया गया है। वर्तमान में इस मार्ग का उपयोग केवल परियोजना निर्माण कार्य में संलग्न वाहनों, मशीनरी एवं अधिकृत कर्मियों द्वारा ही किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोरबा के परियोजना निदेशक अंकित आनंद ने बताया कि निर्माणाधीन बिलासपुर-उरगा खंड पर अनधिकृत आवागमन को रोकने के लिए सभी एंट्री एवं एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए गए हैं। साथ ही, पूरे राजमार्ग में निगरानी के लिए सीसीटीवी सर्विलांस प्रणाली स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद निर्माणाधीन मार्ग पर प्रवेश करने वाले व्यक्तियों एवं

वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एनएचएआई ने सभी नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्माणाधीन मार्ग पर प्रवेश न करें तथा आवागमन के लिए केवल निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें। निर्माणाधीन मार्ग पर अनधिकृत प्रवेश न केवल सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक जोखिमपूर्ण है, बल्कि इससे निर्माण कार्य की गति भी प्रभावित होती है। एनएचएआई सुरक्षित, सुगम एवं विश्वस्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है तथा आम नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा करता है।

पारदर्शी और नियमसम्मत उपयोग सरकार की प्राथमिकता- राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्य शासन ने विभिन्न विभागों, शैक्षणिक संस्थाओं, सहकारी बैंकों, सामाजिक संगठनों और सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं के लिए शासकीय भूमि आवंटन से जुड़े मामलों के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण की दिशा में एक बड़ी पहल की है। इसी कड़ी में आज मंत्रालय में शासकीय भूमि आवंटन संबंधी विचारार्थ अंतरविभागीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

बैठक की मुख्य बातें और निर्णय

यह उच्च स्तरीय बैठक राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी के मार्गदर्शन में विचारार्थ प्रकरण सूची पर विस्तार से चर्चा की गई। 12 महत्वपूर्ण मामलों पर मंथनरू बैठक के दौरान कुल 12 प्रमुख प्रस्तावों पर विचार किया गया। इनमें मुख्य रूप से आवासीय प्रयोजन, बैंक शाखा भवन, सामाजिक भवन, विद्यालय, ऑडिटोरियम निर्माण और विभिन्न संस्थाओं को शासकीय भूमि आवंटन से जुड़े मामले शामिल हैं।

बैठक में रायपुर, धमतरी, कवर्धा और जगदलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त भूमि आवंटन संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत विभागीय परीक्षण रिपोर्ट, आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र, ऑडिट संबंधी

दस्तावेज एवं अन्य विधिक अभिलेखों का बारीकी से परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। राजस्व विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रकरणों की तथ्यात्मक और विधिसम्मत तैयारी समय पर पूरी की जाए, ताकि पात्र संस्थाओं तथा जनहित से जुड़े मामलों का त्वरित निराकरण हो सके।

जनहित और विकास कार्यों को मिलेगी नई गति

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनहित और विकास कार्यों के लिए शासकीय भूमि का पारदर्शी, न्यायसंगत और नियमसम्मत उपयोग सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से हर प्रस्ताव का विधिक, प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं के आधार पर कड़ा परीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में लिए गए निर्णयों से आने वाले समय में प्रदेश के भीतर शिक्षा, बैंकिंग, सामाजिक अधोसंरचना और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार को एक नई गति और मजबूती मिलेगी।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का हुआ आयोजन

शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं, लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करें विद्यार्थी- मंत्री लखन लाल देवांगन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में कोरबा विकासखंड के ग्राम भैंसमा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर, पुष्प भेंट कर एवं मिठाई खिलाकर आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष कोरबा बीजमोती राठिया, अध्यक्ष करतला जनपद अशोका विश्राम कंवर, जिला पंचायत सदस्य रेणुका राठिया, उपाध्यक्ष जनपद करतला मनोज झा, कलेक्टर कुणाल दुदावत, सहायक कलेक्टर ईशान जायसवाल, सीईओ दिनेश नाग, डीईओ टी पी उपाध्याय सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं स्कूली बच्चे व पालक उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा स्वागत गीत से अतिथियों का अभिनंदन किया व आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री देवांगन ने सभी विद्यार्थियों को नवीन शैक्षणिक सत्र के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया सत्र नई ऊर्जा, नए संकल्प और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता। यह जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है, जिसका कभी बंटवारा नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर पूरी मेहनत और लगन से अध्ययन करें, तभी वे सफलता के शिखर तक पहुंच सकेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रतिदिन विद्यालय आने, शिक्षकों का सम्मान करने, अनुशासन का पालन करने तथा देश का जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनने का आह्वान किया।

मंत्री ने कहा कि राज्य शासन की मंशा है कि प्रत्येक बच्चा शिक्षा प्राप्त कर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। परिवार का एक सदस्य शिक्षित होने से पूरा परिवार जागरूक और प्रगतिशील बनता है। इसलिए, शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने अभिभावकों से भी अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने तथा उनकी पढ़ाई-लिखाई में स्वयं रुचि लेने की अपील करते हुए कहा कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) को मिले अधिकारों का लाभ जिले के विकास में प्रभावी रूप से लिया जा रहा है। वद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति, अधोसंरचना विकास तथा मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के अनेक कार्य भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जिससे विद्यार्थी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कलेक्टर श्री दुदावत ने अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने तथा उनकी पढ़ाई पर सतत ध्यान देने की अपील की।

उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर अध्ययन करने, अनुशासन का पालन करने और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की शुभकामनाएं दीं। मुख्य अतिथि मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत विद्यालय के कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल वितरित की। उन्होंने कहा कि इस योजना से दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाली बालिकाओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा मिलेगी तथा बालिका शिक्षा को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

मेधावी विद्यार्थियों एवं उत्कृष्ट शिक्षकों का हुआ सम्मान

इस अवसर पर कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित कर उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान की सराहना की गई।

29 जून से 6 जुलाई तक मनाया जाएगा सहकारिता सप्ताह

रायपुर। सहकारी मंत्रालय की स्थापना के पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक कबीरधाम जिले में सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। सहकारिता के प्रति लोगों को जागरूक करने, सहकारी संस्थाओं की उपलब्धियों से परिचित कराने और जनहित से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सहकारिता सप्ताह के दौरान जिले और सभी विकासखंडों में सहकारिता जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान तथा अन्य जनहितकारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन, समन्वय और नियमित निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि सहकारिता सप्ताह के आयोजन का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।

खास खबर

महिला से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार, तोरवा पुलिस ने भेजा जेल

बिलासपुर। तोरवा थाना पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। महिला संबंधी अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, देवरीडीह निवासी पीड़िता ने 29 जून 2026 को थाना तोरवा में शिकायत दर्ज कराई कि उसी दिन शाम करीब 7:30 बजे मोहल्ले के रहने वाले राम मोंगरे ने उस पर बुरी नीयत से हमला करते हुए उसका हाथ और बांह पकड़कर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता द्वारा पहनी गई लेगिंग भी फाड़ दी। शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। पेट्रोलिंग टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राम मोंगरे, निवासी देवरीडीह, थाना तोरवा, को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 356/2026 के तहत धारा 74 और 296 बीएनएस में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण करने वालों पर कार्यवाही जारी

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पद्मिनी भोई साहू द्वारा दिये गये निर्देश पर खनिज अमला द्वारा 5 दिनों (26, 27, 28, 29 और 30 जून) में जिले के खनिज से जुड़े सभी अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के संदिग्ध क्षेत्र का छापामार कर तत्परता से कार्यवाही किया गया। इससे खनिज के अवैध धंधे में शामिल कारोबारियों को जोर का झटका लगा है। सरिया तहसील में मंगलवार को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान गौण खनिज डोलोमाइट के अवैध परिवहन करते हुए 02 हाइवा वाहन तथा गौण खनिज साधारण रेत के अवैध परिवहन करते हुए 08 ट्रेक्टर वाहन पर कार्यवाही करते हुए थाना सरिया के सुरक्षार्थ में रखा गया। यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई। अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी ।

शराब पार्टी बनी हत्या की वजह, दोस्तों ने युवक की पत्थर से कुचलकर की हत्या

धमतरी। धमतरी जिले में एक हत्या के मामले का खुलासा हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम डाही में एक और सनसनीखेज हत्या हो गई। शराब के नशे में हुए विवाद के बाद दोस्तों ने एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में आठ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। 29 जून की रात करीब 8 से 9 बजे के बीच ग्राम डाही स्थित शीतला मंदिर के सामने टॉवर के पास 8-9 युवक बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान हुलास मंडावी (35 वर्ष) का एक युवक से विवाद हो गया। दोनों के बीच गाली-गलौज शुरू हो गई, जिसे मौजूद लोग शांत कराने का प्रयास कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हुलास मंडावी ने वहां मौजूद अन्य लोगों से भी विवाद शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर आरोपियों ने उसकी हाथ, मुक्कों और डंडों से पिटाई की। इसके बाद एक बड़े पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कुरूद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए कुरूद भेज दिया। वहीं, सभी संदिग्धों को रात में ही हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मामले में करीब आठ आरोपी हैं, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले का जल्द ही विस्तृत खुलासा किया जाएगा।

कंपनी मालिक की बीमारी के आड़ में कर्मचारियों ने किया फर्जीवाड़ा, रकम हड़पकर छोड़ी नौकरी

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। औद्योगिक क्षेत्र स्थित स्वास्तिक इण्डस्ट्रीयल एड कंपनी में अमानत का खयानत का मामला सामने आया है। कंपनी के दो कर्मचारियों ने प्रोपराइटर की बीमारी के नाम पर उनके व्यापसायिक मित्र से 6 लाख से ज्यादा की रकम ली। इसके बाद नौकरी छोड़कर भाग गए। इस बीच कंपनी के संचालक की मृत्यू हो गई। जब वित्तीय लेन-देन में फर्जीवाड़े की बात परिवार के लोगों को पता चली तब यह मामला थाने पहुंचा।

इस मामले में स्वास्तिक इण्डस्ट्रीयल एड के संचालक दिवंगत राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की बेटी सविता श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर थाना पद्मनाभपुर में धारा 318(4), 316 (4) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आवेदिका सविता श्रीवास्तव ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की कम्पनी स्वास्तिक इण्डस्ट्रीयल एड के कर्मचारीगण चाणक्य साहू व संतोष ठाकरे ने उनके नाम का दुरुपयोग कर उनके व्यावसायिक मित्र प्रदीप जैन से 6 लाख 22 रुपए ले लिए। उन्होंने बताया कि उनके पिता राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव का देहांत 8 अप्रैल 2026 की दोपहर 3:00 बजे हो गया था। जब इसकी जानकारी पिताजी के व्यावसायिक मित्र प्रदीप जैन जो कि ताराचद रमेश कुमार नामक फर्म के मालिक हैं उन्होंने आश्चर्यजनक बात बताई। प्रदीप जैन से मेरे पिता का व्यवसायिक लेन देन होता रहता था।

प्रदीप जैन ने देर शाम घर पहुंचे और बताया कि उनके पिता की कंपनी स्वास्तिक इण्डस्ट्रीयल एड के सेल्स एवं मार्केटिंग डिपार्टमेट के कर्मचारी चाणक्य साहू एवं अकाउण्टेन्ट संतोष ठाकरे उनके पास पहुंचे और यह कहकर कि राजेन्द्र श्रीवास्तव अस्पताल में भर्ती है और उन्हें पैसों की आवश्यकता है। दोनों ने प्रदीप जैन से 3 अप्रैल 2026 को 3 लाख रुपए लिए। इसके बाद 8 अप्रैल 2026 को शाम 7.30 बजे 3 लाख 22 रुपए यही बात कहकर लिए। जबकि राजेन्द्र श्रीवास्तव की मृत्यू उसी दिन दोपहर 3 बजे हो चुकी थी।

चाणक्य साहू व संतोष ठाकरे द्वारा उपरोक्त राशि के सबंध में कोई जानकारी कम्पनी के किसी भी कर्मचारी या परिवार के सदस्यों को नहीं दी गई और न ही उक्त रकम उनके द्वारा कम्पनी में जमा किया गया। जब परिवार के सदस्यों ने चाणक्य साहू व संतोष ठाकरे से प्रदीप जैन से लिए गए रकम की जानकारी मांगी गई तो दोनों ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद दोनों ने काम पर आना भी बंद कर दिया। इस तरह दोनों ने मिलकर कंपनी के नाम पर रकम हड़पकर धोखाधड़ी की है। इस मामले में पद्मनाभपुर पुलिस ने चाणक्य साहू व संतोष ठाकरे धारा 318(4), 316 (4) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार हैं।

फरार आरोपी

स्ट्रीट लाइट-पोल से करंट लगने से 2 गायों की मौत, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की मांग

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। कोरबा में मंगलवार रात घंटाघर चौक स्थित वर्धमान ज्वैलर्स के सामने स्ट्रीट लाइट के खंभे में करंट प्रवाहित होने से एक गाय की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए।

पहली घटना से कुछ घंटे पहले पोड़ीबहार क्षेत्र के स्वागत द्वार के पास भी इसी तरह की घटना हुई। करंट प्रवाहित स्ट्रीट लाइट पोल की चपेट में आने से एक अन्य गाय की मौत हो गई। लगातार हुई इन घटनाओं से नगर निगम और विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं।

गौ रक्षक दल ने किया अंतिम संस्कार

दोनों गायों का अंतिम संस्कार गौ रक्षक दल के सदस्यों ने किया। दल ने नगर निगम और बिजली

विभाग से शहर में खुले तारों, करंट प्रवाहित पोल और अन्य विद्युत उपकरणों की तुरंत जांच कराने की मांग की।

गौ रक्षक दल ने चेतावनी दी कि समय पर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो भविष्य में ऐसे हादसों का शिकार केवल पशु ही नहीं, आम नागरिक भी हो सकते हैं। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभागों से विद्युत व्यवस्था सुधारने और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की।

12 साल की बच्ची को बंधक बनाकर किया रेपः पत्नी ने कोर्ट को गुमराह किया

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में 12 साल की बच्ची को बंधक बनाकर जीजा ने उसके साथ रेप किया। मामले में पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार किया है। इस बीच, नाबालिग की मुंहबोली बहन ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर दावा किया था कि उसकी बहन और 9 साल के भाई को अवैध रूप से चाइल्ड हेल्पलाइन में रखा गया है।

दरअसल, बैकुंठपुर के दो अनाथ बच्चे 12 साल की बच्ची और उसका 9 साल का भाई अपनी मुंहबोली दीदी के घर रह रहे थे। आरोप है कि इस दौरान दोनों के साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई। लगातार हो रही प्रताड़ना से परेशान होकर दोनों भाई-बहन दीदी और जीजा के घर से भागकर अपने एक परिचित के यहां पहुंच गए।

मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचना दी गई। इसके बाद दोनों बच्चों की काउंसिलिंग

कराई गई और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें संरक्षण में रखा गया। चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में जब बच्चों से पूछताछ कर काउंसिलिंग की गई, तब पता चला कि उन्हें पनाह देने वाले जीजा ने 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया। इसके साथ ही उसके भाई को भी लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा।

मामला सामने आने के बाद चाइल्ड वेलफेयर सेंटर ने आरोपी जीजा के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं, बच्चों को शेल्टर होम में रखा गया। यह प्रक्रिया अभी चल ही रही थी कि मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश पर कोरिया की कलेक्टर रोक्तिमा यादव, अंबिकापुर के अपर कलेक्टर राम सिंह ठाकुर और महिला-बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने दोनों भाई-बहन को हाईकोर्ट में पेश किया। इस दौरान राज्य शासन की ओर से कोर्ट को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि बच्चों का कल्याण और उनकी मानसिक स्थिति सर्वोपरि है। हाईकोर्ट ने दोनों बच्चों की काउंसिलिंग कोर्ट रूम के बजाय स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी में कराने के निर्देश दिए।

इसके बाद एकेडमी की डायरेक्टर और सीनियर एडवोकेट नौशीना अली की देखरेख में बच्चों की काउंसिलिंग की गई। बच्चों से बातचीत के बाद वह अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंपेंगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने दोनों बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में ही रखने का आदेश दिया है।

कोरबा के हसदेव डैम से युवती ने कूदकर जान दी 10 नंबर गेट पर मिला शव, पुलिस ने जांच शुरू की

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह हसदेव डैम से छलांग लगाकर एक 30 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली। उसका शव डैम के 10 नंबर गेट के पास मिला। सुबह मछली पकड़ रहे मछुआरों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया।

मृतका की पहचान नंदनी मेहर (30) निवासी नीलगिरि सिंचाई कॉलोनी, दर्री थाना के पीछे के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, नंदनी सोमवार सुबह करीब 11 बजे घर से निकली थी और इसके बाद वापस नहीं लौटी। परिवार ने उसकी

काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

मंगलवार सुबह डैम के 10 नंबर गेट के पास मछली पकड़ रहे मछुआरों की नजर पानी में शव पर पड़ी। सूचना मिलते ही दर्री पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर मर्ग पंचनामा की कार्रवाई की। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि नंदनी पार्लर का काम सीखने जाती थी। उसका विवाह नहीं हुआ था। छोटे भाई ने बताया कि सुबह घर पर बहन नहीं मिली। बाद में डैम में युवती का शव मिलने की सूचना पर वह मौके पर पहुंचा, जहां शव की पहचान नंदनी के रूप में हुई।

आत्महत्या के कारणों की जांच जारी

पुलिस के अनुसार, युवती ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसका अभी पता नहीं चल सका है। मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। मौत के वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। दर्री पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

उद्योग लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। सोशल मीडिया के जरिए अधिक मुनाफा कमाने का सपना दिखाकर दोना-पत्तल निर्माण मशीन और कच्चा माल उपलब्ध कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को डीडी नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शैलेन्द्र कुमार रजक बताया जा रहा है। आरोपी पर आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। आरोपी के खिलाफ चंद्रहास वर्मा ने शिकायत की थी।

डीडी नगर पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पीड़ित चंद्रहास वर्मा ने शिकायत की थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि सोशल मीडिया पर दोना-पत्तल उद्योग से संबंधित विज्ञापन देखकर आरोपी से संपर्क किया था।

आरोपी ने खुद को कंपनी संचालक बताते हुए मशीन, कच्चा माल उपलब्ध कराने और तैयार माल खरीदने का भरोसा दिलाया। साथ ही कम समय में अधिक मुनाफा होने का लालच देकर प्रार्थी से अलग-अलग किस्तों में करीब 2.95 लाख रुपए ले लिए।

रुपए मिलने के बाद आरोपी मशीन और कच्चा माल देने में लगातार टालमटोल करता रहा। जब लंबे समय तक कोई सुविधा नहीं मिली तो पीड़ित ने थाना डीडी नगर में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित की शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में सामने आया है, कि आरोपी ने पीड़ित के अलावा छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के 25 से 30 लोगों को भी इसी तरह ठगा है। आरोपी पर आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है।

नशे की हालत का उठाया फायदा, बाइक, मोबाइल और सोने की बाली चुराने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। तोरवा थाना पुलिस ने नशे की हालत में युवक से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और सोने की बाली चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

ग्राम ढेका निवासी श्रवण कुमार ने 27 जून 2026 को थाना तोरवा में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह मुक्तिधाम के पास स्थित शराब भट्ठी के समीप नशे की हालत में था। इसी दौरान दो अज्ञात युवक उसे अपने साथ कुछ दूरी तक ले गए और उसकी नशे की अवस्था का फायदा उठाकर पल्सर मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और सोने की बाली चोरी कर फरार हो गए।

शिकायत के आधार पर थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 464/2026 के तहत धारा 303(3), 3(5) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनीस मसीह (40

वर्ष), निवासी देवरीडीह तथा अरुण उर्फगोलू (20 वर्ष), निवासी देवरीखुर्द, थाना तोरवा के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली। उनकी निशानदेही पर पल्सर मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन और एक सोने की बाली बरामद की गई।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।

5.189 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 5.189 किलोग्राम अवैध गांजा का परिवहन कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा और परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल समेत कुल 2 लाख 80 हजार रुपये की सामग्री जब्त की है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, 30 जून को थाना नंदिनी नगर पुलिस ग्राम मुरमुंदा आम रोड पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल में दो व्यक्ति गांजा लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर मोटरसाइकिल को रोका और तलाशी लेने पर 5.189 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान सन्नी साहू उर्फ माया साहू (27) और त्रिलोचन साहू उर्फ जय प्रकाश (30), दोनों निवासी ग्राम सरोरा, थाना उरला, जिला रायपुर के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना नंदिनी नगर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत अपराध

दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया।

2.80 लाख की सामग्री जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों से करीब 2.50 लाख रुपये कीमत का 5.189 किलोग्राम गांजा तथा 30 हजार रुपये कीमत की मोटरसाइकिल जब्त की। जब्त सामग्री का कुल मूल्य 2 लाख 80 हजार रुपये आंका गया है। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों, अवैध शराब, जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना या नशा मुक्ति हेल्पलाइन 1933 पर दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं गिरीश राज साहू पिता श्री इच्छा राम साहू, निवासी-बोरसी भाठा, पैराडाइज कॉलोनी, दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग छ0ग0 491001 यह शपथकर्ता हूँ कि मैंने अपना यह पुराना नाम गिरीश साहू पिता श्री इच्छाराम साहू को त्यागकर नया नाम गिरीश राज साहू पिता श्री इच्छाराम साहू रख लिया हूँ और पत्नी दीपा साहू निकनेम को सुधार कर शांति साहू आधारकार्ड के हिसाब से है, अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, व अन्य दस्तावेजों मे मेरे नये नाम गिरीश राज साहू पिता श्री इच्छाराम साहू, से ही जाना, पहचाना जाएगा और पत्नी का निक नेम की जगह शांति साहू के नाम से ही जाना, पहचाना जाएगा।

गिरीश राज साहू
पिता श्री इच्छा राम साहू
निवासी- बोरसी भाठा,
पैराडाइज कॉलोनी, दुर्ग, तह. व
जिला दुर्ग छ.ग. 491001

राजनांदगांव में शांति भंग करने पर युवक गिरफ्तार

राजनांदगांव। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के अभियान के तहत लालबाग थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर विवाद कर शांति भंग करने वाले एक युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। आदित्य मसीह (25 वर्ष) निवासी पेंड्री अटल आवास, थाना लालबाग को ट्रांसपोर्ट चौक, पेंड्री के पास अन्य लोगों से विवाद कर शांति भंग करने और संज्ञेय अपराध की आशंका उत्पन्न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तारी की कार्रवाई करते हुए धारा 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसके बाद इस्तगासा तैयार कर आरोपी को माननीय न्यायालय, राजनांदगांव में पेश किया गया।

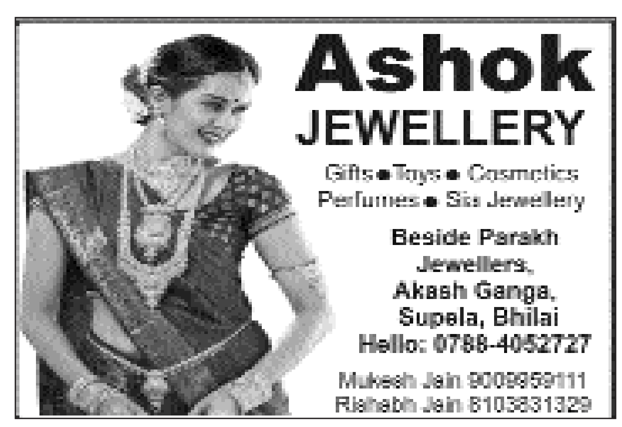

रामगढ़ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक विरासत को विश्व पटल पर दिलाएंगे नई पहचान - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

- रामगढ़ के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा, उदयपुर एवं डूमरडीह को मिलाकर नगर पंचायत बनाने की घोषणा
- मुख्यमंत्री ने 6 पहाड़ी कोरवा बच्चों का कराया शाला प्रवेश, टूरिज्म इन्फ्लूएंसर्स का किया सम्मान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में रामगढ़ महोत्सव-2026 का भव्य समापन

रायपुर। रामगढ़ केवल एक सांस्कृतिक आयोजन का केंद्र नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा, प्रकृति पूजा, आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। सरगुजा की यह पवित्र भूमि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में रामगढ़ का उल्लेख मिलता है, जो इसकी ऐतिहासिक महत्ता को प्रमाणित करता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सरगुजा जिले के ऐतिहासिक दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनश्रुतियों के अनुसार त्रेतायुग में वनवास के दौरान भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण ने इस क्षेत्र में समय व्यतीत किया था। सीताबेंगरा गुफा आज भी श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र है तथा रामगढ़ की हवाओं और शिलाओं में रामायण की स्मृतियां आज भी जीवंत हैं।

उन्होंने कहा कि सीताबेंगरा गुफा भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशालाओं में से एक मानी जाती है, जहां हजारों वर्ष पूर्व सांस्कृतिक आयोजन और नाट्य प्रस्तुतियां होती थीं। वहीं जोगीमारा गुफा अपनी प्राचीन भित्तिचित्र कला के लिए विश्वविख्यात है। हाथीपोल जैसी प्राकृतिक शैल संरचना तथा यहां के प्राचीन शिल्प हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साक्षी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकवि कालिदास द्वारा मेघदूतम् की रचना इसी क्षेत्र में किए जाने का उल्लेख मिलता है, जिससे रामगढ़ का साहित्यिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार रामगढ़, सीताबेंगरा और जोगीमारा जैसी ऐतिहासिक धरोहरों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां पर्यटक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक इस क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित हो सकें। उन्होंने कहा कि जिस भव्यता के साथ इस वर्ष रामगढ़ महोत्सव का आयोजन हुआ है, उसी भव्यता के साथ यह महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा।

ढाई वर्षों में सरगुजा में हुए करोड़ों के विकास कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में सरगुजा जिले में 2,387 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में लोगों के पक्के आवास का सपना तेजी से साकार हो रहा है। 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा प्रतिदिन लगभग 1,600 आवास बनकर तैयार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस के कारण बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है। पुनर्वासित नक्सलियों तथा विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) परिवारों को भी आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। 13 लाख किसानों को दो वर्षों का बकाया बोनस प्रदान किया गया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में प्रतिमाह 1,000 रुपये अंतरित किए जा रहे हैं। रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक 49 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराया गया है।

युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में लगातार भर्ती प्रक्रिया

तीर्थयात्रा दर्शन योजना के अंतर्गत देश के 19 प्रमुख तीर्थस्थलों को शामिल किया गया है, जहां वरिष्ठ नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में लगातार भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही है। आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से लोगों की शिकायतों का प्रभावी समाधान किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रामगढ़ के विकास के लिए 1 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही क्षेत्रवासियों की मांग पर उदयपुर एवं डूमरडीह को मिलाकर नगर पंचायत के गठन की घोषणा भी की।इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि रामगढ़ महोत्सव हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोककला और गौरवशाली परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन का सशक्त माध्यम है। यह आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के साथ-साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने टूरिज्म इन्फ्लूएंसर्स को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंच से विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के छह बच्चों का शाला प्रवेश कराया। उन्होंने बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई तथा स्कूल बैग, वॉटर बॉटल सहित अध्ययन सामग्री प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने 26 से 30 जून तक सरगुजा जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर विशेष डॉक्यूमेंट्री तैयार करने वाले टूरिज्म इन्फ्लूएंसर्स को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सभी को रामगढ़ महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लगभग 50 वर्षों से आयोजित हो रहा यह महोत्सव ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में विधायक प्रबोध मिंज, विधायक रामकुमार टोप्पो, विधायक शकुंतला पोर्ते, विधायक उद्देश्वरी पैंकरा आदि उपस्थित रहे।

मातृशक्ति एवं प्रकृति के प्रति श्रद्धा का अनुपम संगम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने सरगुजा प्रवास के दौरान विकासखंड उदयपुर स्थित रामगढ़ के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस राम वाटिका में स्थापित भगवान श्री राम की प्रतिमा को नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की, इसके साथ ही उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम 3.0 अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान को मातृशक्ति एवं प्रकृति के प्रति श्रद्धा तथा आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि माँ के नाम पर लगाया गया एक पौधा न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक पहल है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं हरित भविष्य की सुदृढ़ आधारशिला भी है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं।

मुख्यमंत्री ने रामगढ़ में निहारी सीताबेंगरा की प्राचीन विरासत, जोगीमारा गुफा का किया अवलोकन

हमारी सांस्कृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य विरासत - मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ऐतिहासिक एवं रामवनगमन पर्यटन परिपथ से जुड़े रामगढ़ में आयोजित दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात सीताबेंगरा गुफा का अवलोकन किया तथा इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं स्थापत्य विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही जोगीमारा गुफा के प्राचीन शिलालेख, भित्तिचित्रों तथा क्षेत्र की अनूठी प्राकृतिक धरोहर हाथीपोल का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि रामगढ़ सरगुजा की हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक चेतना, कला, आस्था और गौरवशाली इतिहास का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात यह स्थल संस्कृति, इतिहास, साहित्य एवं पर्यटन का अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती केवल प्राकृतिक संपदा से ही समृद्ध नहीं है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक विरासत भी विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान रखती है। रामगढ़ जैसी धरोहरें हमारी ऐतिहासिक अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव की अमूल्य निधि हैं, जिनका संरक्षण और संवर्धन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन तथा पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकें और स्थानीय लोगों को भी रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर प्राप्त हों।

उल्लेखनीय है कि रामगढ़ पर्वत की पश्चिमी ढलान पर स्थित सीताबेंगरा एवं जोगीमारा गुफाएँ भारतीय इतिहास, स्थापत्य, शिलालेख एवं चित्रकला की अनुपम धरोहर मानी जाती हैं। मान्यता है कि महाकवि कालिदास ने इन्हीं पहाड़ियों में अपनी कालजयी कृति मेघदूतम् की रचना की थी, जिसका आरंभ आषाढस्य प्रथमदिवसे से होता है। इसी ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आषाढ़ के प्रथम दिवस पर रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। लगभग 44 फीट लंबी सीताबेंगरा गुफा में निर्मित प्राकृतिक रंगमंच, जोगीमारा गुफा में तीसरी-दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की भित्तिचित्र परंपरा तथा यहाँ प्राप्त प्राचीन अभिलेख इस क्षेत्र को विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं।

रामगढ़ की एक अन्य महत्वपूर्ण पहचान हाथीपोल नामक प्राकृतिक सुरंग है। लगभग 180 फीट लंबी तथा 15 से 20 फीट ऊँची यह प्राकृतिक सुरंग अपनी अनूठी संरचना के कारण पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। माना जाता है कि वर्षों तक जल प्रवाह के कारण इसका वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ। सुरंग के दूसरे छोर पर स्थित सीताबेंगरा एवं जोगीमारा गुफाएँ इस सम्पूर्ण क्षेत्र को और अधिक रहस्यमयी, आकर्षक एवं ऐतिहासिक महत्व प्रदान करती हैं। रामगढ़ पर्वत के निचले शिखर पर स्थित इन कलात्मक गुफाओं का संबंध रामायणकालीन परंपराओं से भी जोड़ा जाता है, जिसके कारण यह स्थल धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

निर्माण स्थलों पर बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं: वर्णिका शर्मा

- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बारिश के मौसम में खुले गड्ढों, निर्माणाधीन स्थलों और पानी से भरी नालियों के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ते खतरे को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, जिला कलेक्टरों और नगरीय निकायों के अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि बारिश के दौरान खुले गड्ढों में पानी भर जाने से बच्चों के लिए गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। कई बार खेलते समय या स्कूल आते-जाते बच्चों को गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे उनकी जान तक जोखिम में पड़ जाती है।

आयोग ने नगरीय क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर खुले गड्ढों, नालियों और निर्माणाधीन स्थलों की पहचान करने तथा उन्हें तत्काल भरने या उनके चारों ओर मजबूत बैरिकेडिंग और सुरक्षा घेरा लगाने की अनुशंसा की है। साथ ही

निर्माण एजेंसियों और आवासीय कॉलोनियों को भी निर्देशित करने कहा गया है कि निर्माण कार्यों के लिए खोदे गए गड्ढों को खुला न छोड़ें और उनके आसपास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करें।

डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि संवेदनशील और निर्माणाधीन स्थलों पर आवश्यकता अनुसार चौकीदार या सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं, ताकि बच्चों को संभावित जोखिम से बचाया जा सके। उन्होंने इस विषय को अत्यंत संवेदनशील बताते हुए जिला स्तर पर नियमित समीक्षा करने और संबंधित अधिकारियों को सतत निगरानी रखने की आवश्यकता पर बल दिया। आयोग ने संबंधित विभागों और निकायों से इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करते हुए किए गए उपायों की जानकारी 7 जुलाई 2026 तक उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि बारिश के मौसम में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

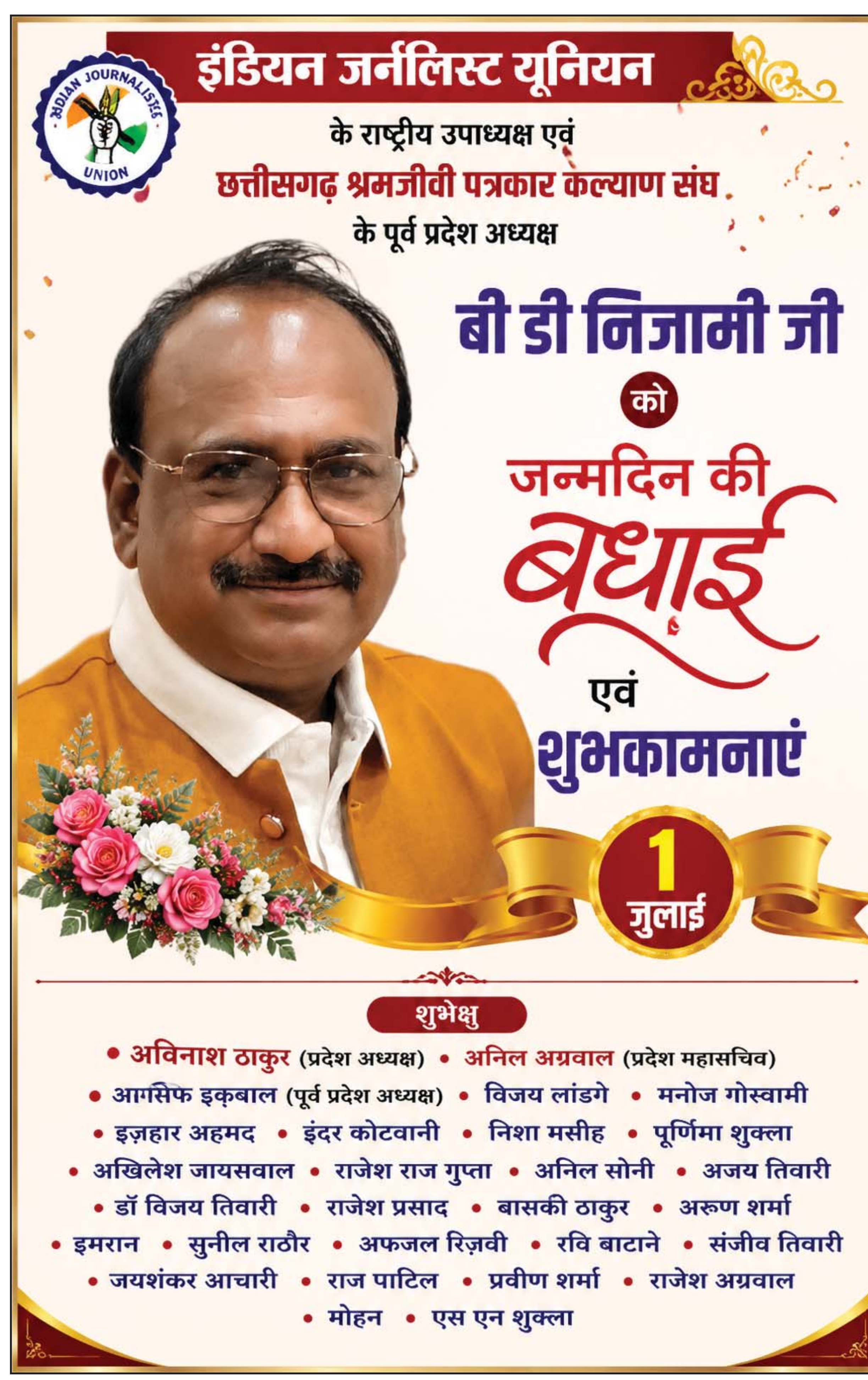

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950